माननीय आरपी सेठी, जेएल गुप्ता और *एनके कपूर से पहले, जे.जे.* मैसर्स यूनाइटेड राइसलैंड लिमिटेड और अन्य, - *याचिकाकर्ता।*

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-प्रतिवादी।

1993 *का*सीडब्ल्यूपी *नंबर*6071

17 अगस्त, 1995

भारत का संविधान, 1950- *अनुच्छेद* 226/227- *हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम,* 1973- धारा 9 एवं 15-ए— *हरियाणा अधिनियम 1991 की संख्या*4 — धारा 9 *निरस्त- धारा*15-ए के *संशोधन के माध्यम से*को *शामिल किया गया जो पूर्वव्यापी प्रकृति की है- विधानमंडल की संभावित और पूर्वव्यापी रूप से कानून बनाने की शक्ति- धारा* 15-ए के संशोधित प्रावधानों को *वैध और संवैधानिक माना गया है ।*

माना गया कि यदि किसी संशोधन क़ानून का उद्देश्य वाक्यांश में दोष या अन्य प्रकृति की त्रुटि को दूर करना और सुधारना है और पहले के अधिनियम के तहत कार्यवाही को मान्य करना है, यहां तक कि न्यायालय द्वारा कुछ दुर्बलताओं के कारण भी ऐसा पाया गया है, तो ऐसे संशोधन और वैधीकरण अधिनियम प्रभावी एवं सार रूप में पूर्वव्यापी संचालन है जिसका उद्देश्य उस उद्देश्य को प्रभावित करना और कार्यान्वित करना है जिसके लिए पहले के प्रमुख अधिनियम में संशोधन और संशोधन किया गया था। ऐसा संशोधन और वैधीकरण अधिनियम जिसका उद्देश्य "लघु त्रुटिओ को संशोधन" करना है, कानून का एक स्वीकार्य तरीका है और अक्सर राजकोषीय अधिनियमों में इसका सहारा लिया जाता है।

(पैरा 35)

इसके अलावा, माना गया कि खरीद कर का भुगतान करने की देनदारी के संबंध में धारा 9 के माध्यम से उत्पन्न संदेह को अधिनियम की धारा 15-ए को प्रतिस्थापित करके और धारा 6 और 15 में उचित संशोधन करके दूर किया जाना था। धारा 15 का प्रभाव यह है कि यदि कोई विशिष्ट छूट नहीं दी गई है तो डीलर के कर योग्य टर्नओवर पर खंड (ए) और (बी) की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट दरों पर

कर लगाया जाएगा। . माना जाता है कि, धारा 9 को हटाने, धारा 15-ए के प्रतिस्थापन और धारा 15 में पूर्वव्यापी संशोधन के बाद याचिकाकर्ताओं के पक्ष में कोई विशिष्ट या निहित छूट अस्तित्व में नहीं है। कर का भुगतान करने का दायित्व है। इसलिए, धारा 15 क साथ पठित धारा 6 द्वारा विनियमित और समायोजन, यदि कोई हो, अधिनियम की धारा 15-ए के तहत स्वीकार्य है। याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम की धारा 15-ए के तहत किसी भी समायोजन का दावा नहीं किया है और यह सही भी है क्योंकि वे निर्यात किए जाने वाले चावल की भूसी के प्रयोजन क लिए उपयोग किए जाने वाले धान की खरीद पर प्रारंभिक कर के भुगतान से छूट का दावा कर रहे हैं।

(पैरा 42)

इसके अलावा, यह माना गया कि समानता के सिद्धांत का अर्थ यह नहीं निकाला जा सकता है कि प्रत्येक कानून का उन सभी व्यक्तियों के लिए सार्वभौमिक अनुप्रयोग होना चाहिए जो स्वभाव, उपलब्धि या परिस्थितियों से नहीं हैं **।**

वही स्थिति. यह सिद्धांत राज्य से वैध उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों को वर्गीकृत करने की शक्ति नहीं छीनता है। विभेदित व्यवहार अपने आप में अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है। यदि कानून समान स्थिति वाले या अच्छी तरह से परिभाषित वर्ग के सदस्यों के साथ समान व्यवहार करता है तो इसे अप्रिय नही माना जा सकता है। यह निर्धारित करना विधायिका का काम है कि वह किन श्रेणियों को मूल क़ानून के दायरे में शामिल करना चाहती है और केवल इसलिए कि कुछ श्रेणियों को छोड़ दिया गया है, इससे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं होता है ।

(पैरा 48)

इसके अलावा, यह माना गया कि क़ानून द्वारा अपेक्षित छूट विशिष्ट और स्पष्ट होनी चाहिए। ऐसी छूट भी दी जा सकती है (अनुमान लगाया जा सकता है बशर्ते कि इस तरह का निष्कर्ष निकालने के लिए मजबूत और ठोस कारण हों। जहां kiक़ानून में विशिष्ठ रूप से छूट मिली है उसे उसे किसी और धरा में उपयोग में लाया नहीं जा सकता है, और छूट का अनुमान लगाने के लिए इसे पंक्तियों के बीच में पढ़कर उसका विश्लेषन करने से गलत प्रक्रिया अपनाई जाती है। विधानमंडल की मंशा जहां भी वांछित हो और छूट देने की शक्ति विशेष रूप से धारा 13, 13-ए और 13-बी में बताई गई है। धार 14 उस बोझ का प्रावधान करती है यह साबित करना कि प्रिंसिपल, एजेंट या किसी अन्य क्षमता के रूप में किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई कोई भी खरीद, बिक्री, आयात या निर्यात इस अधिनियम के तहत कर के लिए उत्तरदायी नहीं है, ऐसे व्यक्तियों पर कर लगाया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता सबूत के ऐसे बोझ का निर्वहन करने में बुरी तरह विफल रहे हैं.

(पैरा 53)

इसके अलावा, यह माना गया कि राज्य विधायिका के द्वारा सन 1991 के अधिनियम संख्या 4 को वैध रूप से कानून बनाने के लिए सक्षम था, जिसके द्वारा धारा 6 और 15 में संबंधित संशोधन करके और एक नई धारा 15-ए को प्रतिस्थापित करके अधिनियम की धारा 9 को हटा दिया गया था। राज्य विधानमंडल देश से बाहर निर्यात किए जाने वाले चावल के निर्माण के उद्देश्य से उपयोग किए जाने वाले धान की खरीद के संबंध में याचिकाकर्ताओं पर कर दायित्व लगाकर इन

प्रावधानों को पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी करने के लिए भी सक्षम था। प्रावधानों के खामियों को दूर करने और यदि कोई हो तो संदेह को दूर करने के घोषित इरादे से अधिनियमित किया गया था, जो कि विधानमंडल द्वारा संदर्भित सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के कारण याचिकाकर्ताओं की कर देयता के संबंध में उत्पन्न हुआ था।

(पैरा 54)

आगे कहा गया है कि छूट का लाभ लेने के लिए, ध्यान में रखा जाने वाला सिद्धांत यह है कि दावा की गई छूट को विशिष्ट दिखाया जाना चाहिए और निहितार्थ से अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए जब तक कि ऐसा निहितार्थ अंतर्निहित न हो और इसमें कोई संदेह न हो।

(पैरा 58)

इसके अलावा, छूट के संबंध में न्यायिक आदेश यह है कि इसे क़ानून द्वारा विशेष रूप से प्रदान किया जाना चाहिए और इसका कड़ाई से अर्थ लगाया जाना चाहिए। यह भी तय है कि यदि करदाता चाहे तो दी गई छूट की भाषा के भीतर मामले को स्पष्ट रूप से बनाने और स्थापित करने के लिए बाध्य है। यह भी उतना ही सच है कि यदि क़ानून द्वारा कर से छूट दी जाती है तो उसे पूर्ण गुंजाइश और आयाम दिया जाना चाहिए और विधायिका या प्रत्यायोजित प्राधिकारी द्वारा इच्छित सीमाओं को लागू करके इसे रोका नहीं जाना चाहिए।

(पैरा 63)

इसके अलावा, यह माना गया कि

(1) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है;

(2) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून का अर्थ ऐसे कानून को सामाजिक परिवर्तनों के अनुरूप लाने के लिए कानून की व्याख्या करना है;

(3) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून न्यायालय के समक्ष विवादग्रस्त मामले के संबंध में होना चाहिए, न कि केवल एक आज्ञाकारी आदेश;

(4) भले ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश को उचित सम्मान और पर्याप्त महत्व दिया जाना आवश्यक है, तथ्यों पर रियायत पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं है;

(5) उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून, दिया गया निर्णय और पारित आदेश उच्च न्यायालय सहित देश के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी प्रकृति के हैं; और

(6) समन्वित पीठों के फैसले पर ऐसी अन्य पीठों द्वारा अपीलीय अदालत के रूप में टिप्पणी या निर्णय नहीं किया जाना चाहिए।

(पैरा 86)

इसके अलावा, यह माना गया कि होटल बालाजी के मामले और मुरली मनोहर के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में, सुप्रीम कोर्ट ने अन्य राज्यों के लिए कानून की व्याख्या करते समय अधिनियम के प्रावधानों का संदर्भ दिया। अन्य राज्यों से संबंधित कानून के प्रावधानों की व्याख्या करते समय सुप्रीम कोर्ट के फैसले में की गई या नोट की गई ऐसी टिप्पणियों या दलीलों को अंतिम रूप से तय नहीं माना जा सकता है क्योंकि माना जाता है कि हरियाणा अधिनियम को स्थगित करने के लिए नहीं कहा गया था। रियायतों पर आगे बढ़ने वाला निर्णय, चाहे वह अंतर्निहित हो या अंतर्निहित और स्वीकार्य रूप से प्रासंगिक प्रावधानों के विश्लेषण या परीक्षण पर नहीं, को संविधान के अनुच्छेद 141 के अर्थ के भीतर कानून घोषित करने वाला नहीं माना जा सकता है। जब इस तरह के ओबिटर हुक्म को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष किसी मुद्दे से विशेष रूप से जुड़ा हुआ नहीं पाया जाता है, तो ओबिटर डिक्टम को मिसाल विशेष के रूप में नहीं माना जा सकता है। हालाँकि, यह स्वीकार किया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश हालांकि कोई प्राथमिकता नहीं है, फिर भी सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ सम्मान और काफी महत्व के योग्य हैं। जो नोट किया गया है और चर्चा की गई है, उसके आलोक में, उपरोक्त दो निर्णयों में निर्धारित कानून को न्यायालय के समक्ष विवादग्रस्त मामले के संबंध में निर्णय नहीं माना जा सकता है।

इसके अलावा, यह मान गया कि अधिनियम की धारा 40 के प्रावधानों का सहारा स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि याचिकाकर्ता को पहले उनकी कर देनदारी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया था और पुनरीक्षण प्राधिकारी ने कथित तौर पर निपटाए गए मामले के रिकॉर्ड मांगने का फैसला किया था। कर का भुगतान करने के लिए याचिकाकर्ताओं की देनदारी का निर्धारण करने वाले आदेश पारित करने से पहले कार्यवाही या उसमें दिए गए आदेशों की वैधता या औचित्य के बारे में खुद को संतुष्ट करने के उद्देश्य से मूल्यांकन प्राधिकारी। यह उल्लेख करना उचित होगा कि पुनरीक्षण प्राधिकारी ने कर की मूल राशि के भुगतान में चूक के मामले में ब्याज का भुगतान करने के लिए उसकी देनदारी के बारे में डीलर को संकेत भी नहीं दिया था। नियम 34 के तहत फॉर्म एसटी 28 पर मूल्यांकन के नोटिस में, मूल्यांकन प्राधिकारी ने ब्याज दर के लिए उस अवधि का उल्लेख नहीं किया है जिस पर अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा 5 के संदर्भ में दायित्व निर्धारित किया गया था। जहां तक मूल्यांकन आदेश ब्याज के भुगतान का निर्देश देता है वह अस्पष्ट और संदिग्ध है जो प्रथम दृष्टया अधिनियम की धारा 25 की उपधारा 5 की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। मामले की परिस्थितियाँ यह नहीं दर्शाती हैं या सुझाव भी नहीं देती हैं कि याचिकाकर्ता-डीलर ने धारा 25 के तहत निर्धारित समय के भीतर कर जमा करने में *दुर्भावनापूर्ण काम किया था और इस प्रकार उपरोक्त धारा की उप-धारा 5 के तहत ब्याज का भुगतान करने के लिए कोई दायित्व उठाया था।*

(पैरा 93)

इसके अलावा, यह माना गया कि बिक्री कर किसी राज्य के लिए राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है और अधिनियम के तहत अधिकारियों को यह तय करना है कि इस तरह के राजस्व की वसूली कैसे और किस तरीके से की जाएगी। कर के भुगतान में चूक की स्थिति में ब्याज के भुगतान का प्रावधान निर्धारिती को राज्य द्वारा निर्धारित समय के भीतर देय कर का भुगतान करने के लिए बाध्य करने का एक साधन है। हालाँकि, यह भी उतना ही सच है कि किसी नागरिक को बिक्री कर के कथित गैर-भुगतान के लिए ब्याज के रूप में जुर्माना देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, जब कर का भुगतान करने का दायित्व स्वयं विवाद में

था *और* अधिकारी स्पष्ट नहीं थे निर्धारिती के दायित्व के बारे में. न तो दोषी करदाता को कानून की तकनीकीताओं के तहत कोई लाभ दिया जा सकता है और न ही राज्य को कर के भुगतान में चूक के मामले में ब्याज का भुगतान करने के दायित्व के भीतर वास्तविक निर्धारिती पर *बोझ डालने की अनुमति दी जा सकती है।*

(पैरा 94)

इसके अलावा, यह माना गया कि ब्याज का भुगतान करने का दायित्व कर का आकलन होने और वैधानिक अवधि के भीतर जमा नहीं होने के बाद ही उत्पन्न होता है। ब्याज का भुगतान करने के लिए कार्रवाई का कारण अधिकारियों द्वारा निर्धारित या करदाता द्वारा सकारात्मक रूप से ज्ञात कर के भुगतान में चूक है। ब्याज लगाने का उद्देश्य डिफ़ॉल्ट के सभी मामलों में समान रूप से लागू होने वाला जुर्माना नही है, चाहे वह वास्तविक हो या अन्यथा।

इसके अलावा, यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता-निर्धारिती ने *दुर्भाविनापूर्ण* या जानबूझकर कर का भुगतान करने से परहेज किया था और इस प्रकार अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा 3 के अर्थ के भीतर ब्याज का भुगतान करने का दायित्व वहन किया था। ब्याज के भुगतान से संबंधित मांग भी अस्पष्ट, अस्पष्ट और कानून के अधिकार के बिना है। याचिकाकर्ताओं को भुगतान के लिए की गई वास्तविक मांग से पहले किसी भी अवधि के लिए ब्याज का भुगतान करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है। अधिनियम के प्रावधानों के तहत खरीद कर। जहाँ तक आक्षेपित आदेश ब्याज के भुगतान का निर्देश देता है, रद्द किये जाने योग्य है।

(पैरा 105)

इसके अलावा, यह माना गया कि (i) 1991 के हरियाणा अधिनियम संख्या 4 के प्रावधान कानूनी, वैध और संवैधानिक हैं;

(ii) 1993 के अधिनियम संख्या 9 द्वारा प्रतिस्थापित अधिनियम की धारा 15-ए के प्रावधान संविधान के प्रावधानों के *अंतर्गत हैं, जो याचिकाकर्ताओं पर* पूर्वव्यापी रूप से खरीद कर का भुगतान करने के दायित्व को सही ढंग से थोपते हैं;

(iii) अधिनियम की धारा 9 को वैध रूप से हटा दिया गया था और इस धारा ने याचिकाकर्ताओं को मांगे गए कर के भुगतान से कोई छूट नहीं दी थी;

(iv) याचिकाकर्ता धान की भूसी के लिए उपयोग किए गए धान पर खरीद कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं, जिसे अंततः देश से बाहर निर्यात किया गया था।

(पैरा 106)

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजा राम अग्रवाल, अधिवक्ता राजेश बिंदल ।

प्रतिवादियों की ओर से अरुण नेहरा, अपर महालेखाकार और अधिवक्ता डीडी वासुदेवा ।

प्रलय

आर . *पी. सेठी, जे.*

(1) कर लगाने की अवधारणा उतनी ही पुरानी है जितनी मानव सभ्यता पुरातन है। नागरिकों को सुरक्षा, सुरक्षा और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार के सभी रूपों द्वारा किसी न किसी रूप में कर एकत्र किया जाता था। यह सुविधाएं प्रदान करने और समाज के महत्वपूर्ण हितों की तलाश के उद्देश्य से, करदाता की ओर से राज्य द्वारा संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण है। पुरातन काल में भी प्रजा की

विकास के साथ राज्य के लाभ के लिए भी अवधारणा किया गया है। संपत्ति के अधिग्रहण के तरीकों और साधनों में भारी बदलाव आया है। कर के भुगतान से बचने के लिए अनिवार्य रूप से कानूनी और अन्य तरीकों का सहारा लेने की मानवीय प्रवृत्ति हमेशा काम करती रही है, जिसमें राज्य और कर लगाने और संग्रह करने वाले दोनों द्वारा अपनाए जाने वाले विरोधी दृष्टिकोण शामिल हैं, जो कि सभी देशों में मौजूद है। ज्ञात इतिहास के दिनों से विश्व। भारत में भी, कराधान प्रणाली के अस्तित्व और शुरुआत का उल्लेख मनु ने अपनी मनु स्मृति में किया है, जिसमें बताया गया है कि बिक्री के लेनदेन पर शुल्क कैसे लगाया जाना चाहिए। मनु ने भी बिक्री कर के अस्तित्व को स्वीकार किया और *कौटिल्य ने* भी। भारत के प्रसिद्ध यात्री मेगस्थनीज ने भी इस तरह के कर के अस्तित्व का उल्लेख किया है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद, कराधान जांच समिति (1924-25) की रिपोर्ट में पहली बार बिक्री कर की कल्पना की गई थी। इस पृष्ठभूमि में और शेष विश्व में बिक्री कर की अवधारणा के विकास के साथ, भारत सरकार अधिनियम संख्या 48 में बिक्री कर लगाने का प्रस्ताव रखा गया था। हालाँकि, भारत के संविधान, 1950 में बिक्री कर लगाने के लिए प्रासंगिक प्रावधान किए गए थे।

Pयह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में एक कर कानून ऐसे बना हुआ है कि उसकी व्याख्या करना कठिन हो गया है। राजकोषीय कानूनों में ऐसी भाषा का उपयोग किया जाता है जिससे बचना कुछ ही लोगों के विवेक पर छोड़ दिया जाता है। यह सभी संबंधित पक्षों द्वारा स्वीकार किया गया है कि देश में व्याख्या करने के लिए सबसे कठिन कानून कराधान से संबंधित कानून है। इस तरह के अधिनियमों में उपयोग की जाने वाली कठिन भाषा और चरण जानबूझकर कर चोरी करने वालों को लड़ने के लिए एक विशाल क्षेत्र प्रदान कर सकते हैं और जानबूझकर चूक करने वालों और कर चोरी करने वालों को कर से बचने के अप्रत्यक्ष उद्देश्य के साथ ऐसी तकनीकी का सहारा लेने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान कर सकते हैं और घोषित कर सकते हैं। आम जनता के प्रयोजनों के लिए लगाया गया है। समय आ गया है कि न केवल कराधान कानून प्रणाली के पुनर्गठन की आवश्यकता है, बल्कि विधायिका द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य को प्रतिबिंबित और प्रदर्शित करने वाली एक स्पष्ट और सक्षम और सहज व्याख्या भी प्रदान की जाए। यह भी स्वीकार किया जाता है कि हमारे कानून निर्माता निश्चित रूप से कानून निर्माता नहीं हैं। कानून निर्माता नौकरशाही के घटक हैं जो स्पष्ट

रूप से 26 जनवरी 1950 को अपनाए गए संविधान की प्रस्तावना में निहित लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं हैं। उचित कार्रवाई करने के लिए समय और आवश्यकता का सहारा लेकर ध्यान दिया जाना वांछित है । कराधान कानून को सरल और आसानी से समझने योग्य बनाकर उपचारात्मक उपाय।

(2) हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 19731 (संक्षेप में 'राज्य अधिनियम') की धारा 9, और 15-ए के दायरे के निर्णय के लिए वर्तमान याचिका दायर करने और इस पीठ के गठन को जन्म देने वाले तथ्य निकाले गए हैं। 1993 के सीडब्ल्यूपी नंबर 6071 से। निर्यात के प्रयोजन के लिए चावल निकालने के लिए उपयोग किए जाने वाले धान पर खरीद कर का भुगतान करने की देनदारी हमारे लिए निर्णय लेने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

(3) याचिकाकर्ता निश्चित रूप से भारत के बाहर चावल के निर्यातक हैं। वे भारत के बाहर चावल के निर्यात के लिए धान की भूसी निकालने के उद्देश्य से पंजाब और हरियाणा राज्यों के साथ-साथ अन्य राज्यों से भी धान खरीदते हैं। याचिकाकर्ताओं ने देश के लिए बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित करने का दावा किया है। धान को केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम (संक्षेप में केंद्रीय अधिनियम) की धारा 14 के तहत वस्तु घोषित किया गया है। केंद्रीय अधिनियम की धारा 15 राज्य के भीतर घोषित वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर कर के संबंध में प्रतिबंध और शर्तें निर्धारित करती है। यह प्रावधान करता है कि राज्य का प्रत्येक बिक्री कर कानून, जहां तक यह घोषित वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर कर लगाता है या लगाने का अधिकार देता है, इस शर्त सहित विभिन्न शर्तों के अधीन होगा: -

> "जहां धारा 14 के खंड (1) के उप खंड (i) में निर्दिष्ट किसी भी धान की राज्य के अंदर बिक्री या खरीद के संबंध में उस कानून के तहत कर लगाया गया है, ऐसे में खरीदे गए चावल पर टैक्स लगाया जाएगा। ऐसे धान पर लगाए जाने वाले कर की मात्रा कम कर दी जाएगी।"

(4) अनुसूची *डी*धान पर कर लगाने के बिंदु को राज्य के भीतर पहली बिक्री के रूप में निर्धारित करती है, जब एक डीलर बाहर से आयात करने पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है, और लेवी का चरण राज्य के भीतर एक उत्तरदायी डीलर द्वारा अंतिम खरीद है। जब धान की ऐसी खरीद राज्य के भीतर की जाती है तो कर का भुगतान करें। मूल्यांकन प्राधिकारी ने याचिकाकर्ताओं को

राज्य अधिनियम के तहत किसी भी खरीद कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया। निर्धारण प्राधिकारी ने 'शून्य' की मांग बनाई और याचिकाकर्ताओं ने रिफंड के विभिन्न समायोजन करने के बाद मांग को पूरा करने के लिए शेष राशि जमा कर ली। उप उत्पाद एवं कराधान आयुक्त (निरीक्षण)-सह-पुनरीक्षण प्राधिकारी, कामा! अधिनियम की धारा 40 के तहत एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें नोटिस में उल्लिखित राशि के धान के खरीद मूल्य के लिए अधिनियम की धारा 15-ए के तहत अनुमत समायोजन के संबंध में स्वत: कार्रवाई करने का प्रस्ताव दिया गया, जिसमें से चावल खरीदा *गया*। भारत के बाहर निर्यात के दौरान बेचा गया था। यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने धारा 9 के तहत छूट का आनंद लिया

अधिनियम और उस अवधि के लिए कर का भुगतान करने के लिए निर्देशित नहीं किया जा सकता था जब धारा 9 को क़ानून की किताब में स्वीकार किया गया था। आगे यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ताओं को फॉर्म एसटी-3आई में प्रमाण पत्र दिया गया है जिसके तहत वे कर के भुगतान के बिना चावल के निर्यात के लिए धान खरीदने के हकदार थे। यह प्रस्तुत किया गया है कि अन्य वस्तुओं के संबंध में अनुमति देते हुए धान के मामले में रिफंड या समायोजन से इनकार करना अनुच्छेद 14, 19 (1) (जी), 286, 301, 302, 304 और 300 के प्रावधानों का उल्लंघन है। -भारत के संविधान की धारा ए के अलावा केंद्रीय अधिनियम की धारा 5 और 15 (सी) और राज्य अधिनियम की धारा 9 और 12 का उल्लंघन है। 1992 के हरियाणा अध्यादेश संख्या 1 और 1993 के अधिनियम संख्या 9 द्वारा प्रतिस्थापित राज्य अधिनियम की धारा 15-ए को असंवैधानिक और शून्य घोषित किए जाने योग्य बताया गया है।

(5) *अनुलग्नक* पी/आई के माध्यम से, प्रतिवादी संख्या 2 उप उत्पाद एवं कराधान आयुक्त-सह-पुनरीक्षण प्राधिकारी ने अधिनियम की धारा 40 के तहत एक नोटिस जारी किया जिसमें याचिकाकर्ताओं को सूचित किया गया कि उन्होंने वैधता के बारे में खुद को संतुष्ट करने के लिए स्वत: संज्ञान लेते हुए उनके बिक्री कर मूल्यांकन रिकॉर्ड की जांच की है / और मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की औचित्य और उक्त रिकॉर्ड की जांच करने के बाद उन्होंने मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा पारित मूल्यांकन आदेश में विसंगतियां पाईं, जिसके कारण मूल्यांकन आदेश में संशोधन करना पड़ा। पुनरीक्षण के तहत आदेश पारित करने

से पहले, याचिकाकर्ताओं को उनके कार्यालय में सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया था और उनके दावे के समर्थन में खाता बही/स्टॉक सूची/पर्याप्त साक्ष्य, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया था। उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के खिलाफ रिट याचिकाएं मुख्य रूप से इस आधार पर दायर की गई हैं कि उक्त नोटिस अधिकार क्षेत्र के बिना था और याचिकाकर्ताओं के मामले में लागू कानून के प्रावधानों के आधार पर जारी किया गया था। मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा जिन प्रावधानों पर भरोस किया गया है, उन्हें असंवैधानिक और शून्य बताया गया है।

(6) प्रतिवादियों की ओर से दाखिल जवाब में माना गया कि याचिकाकर्ता पंजीकृत डीलर हैं और चावल शेल्टर चला रहे हैं. यह स्वीकार किया गया है कि वे हरियाणा की मंडियों (बाजारों) के साथ-साथ हरियाणा राज्य के बाहर से धान खरीदते थे और चावल को छीलने के बाद भारत के बाहर विभिन्न देशों में निर्यात करते थे। केंद्रीय अधिनियम की धारा 14 के तहत धान और चावल को अलग और विशिष्ट घोषित माल बताया गया है। धान और चावल दो अलग-अलग वस्तुएं हैं और इन पर राज्य अधिनियम की धारा 17 और अनुसूची 'डी' के साथ पठित धारा 6 के तहत कर लगाया जा सकता है। राज्य में धान की अंतिम खरीद पर टैक्स के अधीन डीलर को टैक्सी का भुगतान करना पड़ता है।

स्कुउउ *यू ओय.* कहा गया है कि केंद्रीय अधिनियम केवल उन लोगों पर लागू होता है, जिनका उल्लेख उन उद्देश्यों में किया गया है, जिन्हें भारत के क्षेत्र के बाहर बेचा जाता है, क्योंकि केंद्रीय अधिनियम 5 ('जे) में कहा गया है कि उप-धारा (1) में किसी भी बात के बावजूद धारा 5, बिक्री या खरीद से पहले की अंतिम बिक्री या खरीद ओआई गुंडों द्वारा भारत के बाहर मेरे क्षेत्र से बाहर माल के निर्यात को भी इस तरह के निर्यात के पाठ्यक्रम में माना जाएगा, इस तरह की बिक्री या खरीद कर स्थान परिवर्तन, और उद्देश्य के लिए था ऐसे निर्यात के लिए या उसके संबंध में समझौते या आदेश का अनुपालन करना। विभिन्न निर्णयों के आधार पर, यह प्रस्तुत किया गया है कि यदि खरीद कुछ वस्तुओं की है जिन्हें बाद में भारत के क्षेत्र से बाहर निर्यात किया गय था तो ऐसी खरीद छूट है लेकिन यदि सामान भारत के क्षेत्र के अलावा किसी अन्य स्थान पर खरीदे जाने पर स्थानीय अधिनियम के तहत कर लगाया जा सकता है और उस स्थिति में केंद्रीय अधिनियम के धारा 5(3) के प्रावधान लागू नहीं होंगे। यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता निर्यात करते हैं चावल भारत के क्षेत्र से बाहर है और निर्धारण प्राधिकारी ने इस प्रकार निर्यात किए गए चावल पर कोई कर नहीं लगाया है। याचिकाकर्ता हरियाणा राज्य में धान की ऐसी खरीद के दौरान अनुसूची 'डी' के साथ पठित राज्य अधिनियम की धारा 6, 15-ए और 17 के तहत धान पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। याचिकाकर्ताओं को केंद्रीय अधिनियम की धारा 5 (3) के लाभ के हकदार नहीं होने के कारण हरियाणा राज्य के भीतर अंतिम खरीद होने के कारण धान पर खरीद कर का भुगतान करने के लिए कानूनी दायित्व के तहत बताया गया है। कहा गया है कि याचिकाकर्ता के पास कोई मामला नहीं है क्योंकि केंद्रीय अधिनियम की धारा 14 के प्रावधानों के अनुसार भी धान और चावल दो अलग-अलग वस्तुएं हैं और एक और दूसरे से अलग हैं। याचिकाकर्ता अपनी देनदारी तभी बचा सकते थे जब उन्होंने धान का निर्यात किया होता, लेकिन चूंकि उन्होंने चावल का निर्यात किया है, इसलिए वे इस पर खरीद कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

(7) पक्षों के लिए संयुक्त वकील के प्रतिद्वंद्वी तर्क का उल्लेख करने से पहले, मामले में लागू कानून के प्रावधानों के विशेष संदर्भ के साथ हरियाणा अधिनियम की उत्पत्ति, योजना और उद्देश्य का उल्लेख करना उपयोगी होगा।

(8) राज्य अधिनियम, 1973 का अधिनियम संख्या 20, हरियाणा राज्य में कुछ वस्तुओं की खरीद की बिक्री पर कर लगाने को वैध बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम आवश्यक हो गया था क्योंकि पंजाब जनरल सेल्स टैक्स अधिनियम, 1948 के कामकाज के अनुभव से कुछ अस्पष्टताएं और अपर्याप्तताएं प्रकाश में आई हैं। उद्देश्य एवं कारणों में यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि मूल अधिनियम में समय-समय पर कई संशोधन शामिल किए गए हैं

समय के साथ और मौजूदा अधिनियम क प्रावधानों को समझने, व्याख्या करने और लागू करने में निर्धारितियों द्वारा एक बड़ी कठिनाई महसूस की जा रही थी , हरियाणा राज्य में 1973 का नया अधिनियम संख्या 20 अधिनियमित किया गया था। यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि माल की बिक्री पर कर लगाने का प्रावधान पहली बार भारत सरकार अधिनियम, 1935 में प्रांतों के राजस्व को बढ़ाने के उद्देश्य से शामिल किया गया था। मद्रास राज्य वर्ष 1939 में सामान्य बिक्री कर कानून बनाने वाला पहला राज्य था, जिसे बाद में 1941 के अधिनियम संख्या 4 द्वारा लागू किया गया था। वर्ष 1948 मे देश के विभाजन के बाद, उक्त अधिनियम को 1948 के अधिनियम संख्या 46 द्वारा निरस्त कर दिया गया था। 1947. 1 नवंबर, 1966 को पंजाब और हरियाणा राज्यों के पुनर्गठन के बाद 3 मई, 1973 को नया अधिनियम शामिल होने तक पंजाब अधिनियम हरियाणा राज्य में भी लागू रहा। इस अधिनियम में भी संशोधन किया गया था । विभिन्न अवसरों पर महसूस की गई जरूरतों, जरूरतों और आवश्यकताओं के अनुसार।

(9) राज्य अधिनियम की धारा 2 डीलर, व्यापार, घोषित माल, निर्यात करना, माल, आयात, खरीद, बिक्री, कारोबार की परिभाषा सहित विभिन्न परिभाषाओं से संबंधित है। अध्याय 11 कर निर्धारण प्राधिकारी और न्यायाधिकरण को निर्धारित करता है। धारा 3 राज्य को एक व्यक्ति को आयुक्त नियुक्त करने और उसकी सहायता के लिए ऐसे अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करने का अधिकार देती है जो उचित समझे जाएं। आयुक्त के पास पूरे राज्य पर अधिकार क्षेत्र है और वह प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करता है और अधिनियम द्वारा या उसके तहत उस पर लगाए गए सभी कर्तव्यों का पालन करता है। धारा 4 ट्रिब्यूनल के संविधान से संबंधित है जिसमें एक सदस्य होता है जिसे राज्य सरकार द्वारा ऐसे कार्यों को करने और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए नियुक्त किया जाता है जो ट्रिब्यूनल को अधिनियम द्वारा या उसके तहत सौंपी या प्रदत्त की जा सकती हैं। धारा 6 से 18 तक कर की घटना और उद्ग्रहण से संबंधित है। अध्याय IV कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी डीलर के अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान करता है और अध्याय V रिटर्न, मूल्यांकन,

पुनर्मूल्यांकन और संग्रह से संबंधित है। अध्याय VI खातों के रखरखाव, व्यावसायिक परिसरों और खातों के निरीक्षण, चेक पोस्ट की स्थापना और समाशोधन और अग्रेषण एजेंटों द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने आदि से संबंधित है। अध्याय VII अपील, संशोधन, समीक्षा और धनवापसी से संबंधित है। धारा 40 आयुक्त को किसी भी कार्यवाही की वैधता या औचित्य के बारे में खुद को संतुष्ट करने के उद्देश्य से, ट्रिब्यूनल के अलावा किसी भी मूल्यांकन प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष लंबित या निपटाए गए किसी भी मामले का रिकॉर्ड मांगने के लिए अधिकृत करती है। अध्याय VIII अपराध और दंड से संबंधित है जबकि अध्याय IX विविध है।

(10) श्री राजा राम अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, जिन्होंने याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस शुरू की, ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी-पुनरीक्षण प्राधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करना उचित नहीं था क्योंकि उनके अनुसार याचिकाकर्ता खरीद कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं थे। धान का उपयोग धान की भूसी निकालने के लिए किया जाता है जिसे देश से बाहर निर्यात किया जाता है। उन्होंने तर्क दिया है कि अधिनियम की धारा 9 के तहत याचिकाकर्ताओं को पहले से ही खरीद कर के भुगतान से छूट का हकदार माना गया है और इस धारा के निरस्त होने से याचिकाकर्ता धारा 15 या धारा 17 के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं बनता है। राज्य अधिनियम. यह प्रस्तुत किया गया है कि 1993 के अधिनियम संख्या 9 के *तहत* धारा 15-ए को शामिल करने से याचिकाकर्ता के उन अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा जो अधिनियम की निरस्त धारा 9 के तहत उन्हें प्राप्त हुए थे। वैकल्पिक रूप से यह तर्क दिया जाता है कि अधिनियम की धारा 15-ए संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है क्योंकि इसका उद्देश्य समान स्थिति वाले व्यक्तियों के बीच भेदभाव करना है। यह तर्क दिया गया है कि चावल के निर्यात से निपटने वाले डीलरों के संबंध में और खरीद कर के भुगतान के दायरे से बाहर छोड़े गए डीलरों के संबंध में किए गए भेदभाव का प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ कोई संबंध या औचित्य नहीं था। आगे यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता किसी भी तरह से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, खासकर जब उनके कृत्यों को *प्रामाणिक* माना गया है और किसी बाहरी विचार से प्रेरित नहीं किया गया है। शीर्ष न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर भरोसा करते हुए, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किय है कि यदि राज्य द्वारा अधिनियमित कानून की व्याख्या निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार की जाती है, तो याचिकाकर्ताओं को किसी भी कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है । यह प्रस्तुत किया गया है कि यदि कुछ शब्दों या शर्तों के दो निर्माण संभव ह तो न्यायालय को उस निर्माण के पक्ष में झुकना चाहिए जो नागरिक को राहत दे। आगे यह तर्क दिया गया कि अधिनियम की धारा 9 एक विशेष प्रावधान थी और धारा 17 चार्जिंग धारा नहीं थी।

(11) निर्धारितियों के एक अन्य समूह की ओर से पेश हुए वकील श्री एमएल वर्मा ने श्री राजा राम अग्रवाल के अधिकांश तर्कों को अपनाया और अधिनियम की

धारा 17 को चार्ज करने वाली धारा नहीं होने के संबंध में प्रस्तुतियाँ विस्तृत कीं। उनका जोर इस बात पर था कि राज्य अधिनियम की धारा 6 एकमात्र आरोप लगाने वाली धारा थी और विवादित धाराएं संविधान के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करती थीं।

(12) जवाब में अरुण नेहरा जी. प्रस्तुत किया गया कि धारा 9 याचिकाकर्ताओं के मामले में लागू नहीं थी और यदि इसे लागू माना भी जाता है तो यह याचिकाकर्ताओं को कर का भुगतान करने के दायित्व से मुक्त नहीं करता है। उनके मुताबिक धारा 6, 9, 15-ए और 17

चार्जिंग अनुभाग हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि कर के भुगतान से छूट नहीं मानी जा सकती क्योंकि इसे विशिष्ट और स्पष्ट होना आवश्यक है। उनके अनुसार अधिनियम के तहत विभिन्न धाराएं विशेष रूप से छूट से संबंधित हैं और ऐसी धाराएं उन छूटों से संबंधित नहीं हैं जैसा कि याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है। विद्वान वकील के अनुसार, याचिकाकर्ताओं ने जिन निर्णयों पर भरोसा किया! या तो मामले में लागू नहीं थे या किसी भी तरह से उनके तर्कों का समर्थन नहीं करते थे।

(13) अपने प्रतिद्वंद्वियों के विवादों की सराहना करने से पहले, यह समझना आवश्यक है कि कर, विशेष रूप से बिक्री और खरीद कर का क्या मतलब है। एक सभ्य समाज में कर को कानून द्वारा लागू किए जाने योग्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा धन की अनिवार्य निकासी के रूप में मान्यता दी जाती है। यह विधानमंडल द्वारा सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए धन जुटाने के लिए व्यक्तियों या संपत्ति पर लगाया गया आरोप है और इसे सरकार के समर्थन और सभी सार्वजनिक जरूरतों के लिए राज्य के प्राधिकारी द्वारा लागू किया जाता है। यह नहीं भुलाया जा सकता कि कर का भुगतान स्वैच्छिक नहीं माना जा सकता क्योंकि इसने लोगों की इच्छा को व्यक्त करते हुए विधायिका द्वारा उत्तरदायी व्यक्ति पर अनिवार्य कर लगाने को अधिकृत किया है। कर कभी भी करदाता की सहमति से नहीं लगाया जाता है। इसलिए, इसमें परिकल्पना की गई है कि कर लगाने के सभी मामलों में राज्य और निर्धारिती का विरोधी रवैया होना चाहिए। चूंकि कर एक घोषित सार्वजनिक उद्देश्य के लिए लगाया जाता है, इसलिए

न्यायालयों पर राजकोषीय कानून की इस तरह से व्याख्या करने का कर्तव्य बनता है जो किसी भी तरह से ऐसे सार्वजनिक उद्देश्य को विफल नहीं करता है। कर लगाना निश्चित रूप से राज्य की संप्रभुता का एक स्वीकृत कार्य है जो लोगों की इच्छा के माध्यम से प्रतिबिंबित और प्रदर्शित होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व विधायिका और लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित और गठित सरकार द्वारा किया जाता है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, विशेष रूप से भारत जैसे विकासशील देश में, वादा या विचार की गई योजनाओं और परियोजनाओं को लागू करने के लिए लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना राज्य का प्राथमिक कर्तव्य बन जाता है। पूरा हुआ. यह सर्वमान्य स्थिति है कि चूंकि कर लगाने का उद्देश्य जनता की भलाई के लिए धन जुटाना है, इसलिए यह विधानमंडल का कर्तव्य है कि वह सामाजिक, आर्थिक और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कर लगाए जाने वाले व्यक्ति, लेनदेन या वस्तुओं के दायित्व के संबंध में निर्णय ले। प्रशासनिक विचार. न्यायालय विधिवत निर्वाचित विधायिका के माध्यम से व्यक्त राज्य की घोषित आर्थिक और सामाजिक नीति के स्थान पर अपनी राय नहीं दे सकते। विभिन्न न्यायालयों द्वारा यह सही माना गया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में शक्ति की शक्ति होती है
कराधान विधायिका में निहित है न कि कार्यपालिका या न्यायपालिका में। कर को शुल्क या अन्य योगदान के साथ बराबर नहीं किया जा सकता। बिक्री कर एक ऐसा कर है जिसमें इसके दायरे में व्यापार के साथ-साथ खुदरा बिक्री, संपूर्ण नौकायन या विनिर्माण चरण में सभी मूर्त व्यक्तिगत संपत्ति शामिल है, कर कानून में उल्लिखित अपवादों के साथ।

(14) खरीद कर माल की खरीद पर लगाया जाने वाला एक कर है जो नकद या विलंबित भुगतान या अन्य उपलब्ध विचारों के लिए ऐसे माल के अधिग्रहण के समय लगाया जाता है, अन्यथा ऐसे खरीद कर लगाने के लिए प्रदान करने वाले क़ानून में उल्लिखित परिस्थितियों के अलावा। आम तौर पर बिक्री कर बिक्री के अवसर पर लगाया जाने वाला कर है जबकि खरीद कर खरीद के अवसर पर लगाया जाने वाला कर है। जिस लेन-देन में किसी के द्वारा बिक्री शामिल होती है, उसमें आवश्यक रूप से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा खरीदारी शामिल होती है। बिक्री

और खरीद एक ही लेन-देन को संबंधित व्यक्तियों के अलग-अलग नजरिए से देखने के महज अलग-अलग तरीके हैं।

(15) बिक्री कर क़ानूनों को मोटे तौर पर दो वर्गों में विभाजित किया गया है यानी एक एकाधिक बिंदु कर लगाने वाला और दूसरा लेनदेन की श्रृंखला में एकल बिंदु कर लगाने वाला। कुछ राज्यों में, विशेष रूप से महाराष्ट्र में, दोहरी बिंदु प्रणाली भी विकसित की गई थी। मल्टी प्वाइंट सिस्टम बिक्री की प्रत्येक घटना पर कराधान प्रदान करता है और सिंगल प्वाइंट सिस्टम एक घटना और नियंत्रित प्रणाली है जहां कर लगाया जाता है, पहले डीलर से आखिरी तक लेख के पारित होने में, जो डीलरों की पूरी श्रृंखला हो सकती है, है अंतिम बिक्री से जुड़े डीलरों की संख्या को नजरअंदाज करते हुए, लिंक की मध्यवर्ती संख्या द्वारा निर्णय लेने के लिए नहीं छोड़ा गया है। सभी मामलों में अधिनियम के तहत बिक्री कर का भुगतान करने का दायित्व केवल विक्रेता और खरीदार पर है।

(16) इस संदर्भ में याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने कराधान कानूनों की व्याख्या के संबंध में न्यायालय की शक्तियों को नियंत्रित करने, निर्धारित करने और सीमित करने वाले विभिन्न निर्णयों का उल्लेख किया है। '*आयकर आयुक्त* बनाम ***स्ट्रेन*** *बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी* ***लिमिटेड*** (1)' पर आश्रय लेते हुए । यह तर्क दिया गया है, "यह याद रखना आवश्यक है कि जब किसी औद्योगिक गतिविधि को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कर की रियायती दरों का प्रावधान करने वाले कानून के संदर्भ में कोई प्रावधान किया जाता है तो क़ानून की भाषा में एक उदार निर्माण किया जाना चाहिए। ”

(1) एटीआर 1989 एससी 1490।

(17) '*बजाज टेम्पोस लिमिटेड, बॉम्बे*बनाम *कमिश्नर ऑफ टीटी*' (2) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "विधानमंडल लोगों की जरूरतों का सबसे अच्छा न्यायाधीश था, समय-समय पर संशोधन, प्रतिस्थापन और चूक के माध्यम से अपना इरादा प्रकट करता था। " सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए।” न्यायालय ऐसी व्याख्या और निर्माण का सहारा लेते हैं जो विधानमंडल द्वारा अधिनियमित

अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के अनुरूप प्रावधान को सार्थक बनाने के लिए उचित और उद्देश्यपूर्ण है।

(18) नागरिक का अधिकार बनाने या नागरिक का अधिकार छीनने वाले वैधानिक प्रावधानों को आम तौर पर संभावित माना जाता है। उन्हें केवल तभी पूर्वव्यापी माना जाएगा यदि व्यक्त शब्दों या आवश्यक निहितार्थ द्वारा विधायिका ने उन्हें इस रूप में लागू किया हो। पूर्वव्यापी कार्रवाई केवल उस सीमा तक ही सीमित होगी जिस सीमा तक इसे ऐसा बनाया गया था। विधायिका का इरादा हमेशा उसके द्वारा उपयोग किए गए शब्दों से इकट्ठा किया जाता है, शब्दों को उनका स्पष्ट, सामान्य, व्याकरणिक अर्थ दिया जाता है।

(19) *महादेवलाल* में.वि. _ *पश्चिम बंगाल के प्रशासक जनरल*(3). सुप्रीम कोर्ट ने क़ानूनों की व्याख्या में लागू विभिन्न नियमों पर विचार किया और माना कि, "कानून के लाभकारी उद्देश्य को आगे बढ़ाने की चिंता में, अदालतों को अस्पष्टता की तलाश करने के प्रलोभन में नहीं आना चाहिए, जब कोई नहीं है।" इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित क़ानून की व्याख्या के चार नियम हैं: -

> **"इनमें से पहला यह है कि मूल** अधिकारों का निर्माण करने वाले या मूल अधिकारों को छीनने वाले वैधानिक प्रावधान **आम तौर पर** संभावित होते हैं: वे केवल पूर्वव्यापी होते हैं यदि **व्यक्त** शब्दों द्वारा या आवश्यक निहितार्थ **द्वारा** विधायिका ने उन्हें पूर्वव्यापी **बना दिया हो ;** और पूर्वव्यापी कार्रवाई केवल उस सीमा तक ही सीमित **होगी जहां तक इसे** व्यक्त शब्दों या आवश्यक निहितार्थों **द्वारा बनाया गया है ।** दूसरा नियम यह है कि प्रयुक्त शब्दों **का** अभिप्राय यह है। शब्दों को उनका स्पष्ट, सामान्य, व्याकरणिक **अर्थ देना । तीसरा** नियम यह है कि यदि किसी विधान में

(2) **एआईआर 1992 एससी 1622।**

(3) एआईआर 1960 एससी 936।

> सामान्य उद्देश्य या जो किसी विशेष वर्ग के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना हो, कोई भी प्रावधान अस्पष्ट होता है इसलिए वह दो अर्थों में सक्षम होता है, एक वह जो लाभ को सुरक्षित रखेगा और दूसरा जो उसे छीन लेगा, वही अर्थ अपनाया जाना चाहिए जो उसे सुरक्षित रखता है। चौथा नियम यह है कि यदि सख्त व्याकरणिक व्याख्या किसी बेतुकेपन या असंगति को जन्म देती है तो ऐसी व्याख्या को खारिज कर दिया जाना चाहिए और एक ऐसी व्याख्या जो उस उद्देश्य को प्रभावी करेगी जो विधायिका के लिए उचित माना जा सकता है, यदि आवश्यक हो तो शब्दों पर रखा जाएगा। यहाँ तक कि प्रयुक्त भाषा में संशोधन करके भी।"

(21) उनकी अदालतों से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वे नीति बनाने वाले विनियमन द्वारा निर्धारित नीति के गुण और दोषों की जांच करें। किसी नियम या विनियम में शामिल नीति में कोई भी खामी क़ानून को अधिकार *क्षेत्र* से बाहर नहीं कर देगी और न्यायालय, अपनी राय में, यह नहीं मान सकता कि नीति बुद्धिमानी या मूर्खतापूर्ण नहीं थी। *महाराष्ट्र एसबीओ* और *एचएस एजुकेशन* बनाम *परितोष भूपेश* (4) में , यह आयोजित किया गया था: -

> "किसी विनियमन की संवैधानिकता को केवल तीन गुना परीक्षण द्वारा तय किया जाना चाहिए, अर्थात् (1) क्या ऐसे नियमों के प्रावधान प्रतिनिधि को क़ानून द्वारा प्रदत्त शक्ति के दायरे और दायरे में आते हैं; (2) क्या प्रतिनिधि द्वारा बनाए गए नियम/विनियम मूल अधिनियम के प्रावधानों के साथ किसी भी हद तक असंगत हैं और अंत में (3) क्या वे किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं या संविधान द्वारा लगाए गए अन्य प्रतिबंधों या सीमाओं का उल्लंघन करते हैं।

(22) अगैअगेन' के '*एम/एसपीएच अफालिटरफार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड एस* बनाम *यूएसटैट महाराष्ट्र और अन्य*' (5) मामले में कोर्ट ने कहा: -

" सबसे अच्छी व्याख्या संदर्भ से की जाती है। *मुझे अभी भी निरीक्षण करना है, - उत्तर देने के लिए न्यायिक प्रस्ताव का एक अतिरिक्त भाग।* यह अन्यायपूर्ण है।

> पूरे कानून की जांच किए बिना कानून के किसी विशेष भाग के बारे में निर्णय लेना या प्रतिक्रिया देना । इंटरप्रेटरेट कॉन-कॉर्डरे लेजिस लेगिबस, एस्ट ऑप्टिमस इंटेप्रेटेन्डी मोडस। व्याख्या करना और इस तरह से कि कानूनों के साथ कानूनों का सामंजस्य हो, व्याख्या का सबसे अच्छा तरीका है..."

(23) जहां अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के संदर्भ में राष्ट्रीय कानूनी प्रणाली के बारे में संदेह है, वहां कानून की व्याख्या, जब भी संभव हो, संयोजकों की भावना को ध्यान में रखते हुए सामंजस्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए।

(24) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने *'एमसी मोनागल* बनाम *वेस्टमिंस्टर सिटी काउंसिल'* (6), और *'पिकस्टोन और अन्य-वी' का भी उल्लेख किया है। फ्रीमास पीएलसी?* (7), उनके इस तर्क के समर्थन में कि वैधानिक व्याख्याओं के लिए, विधानमंडल की मंशा सुनिश्चित करने के लिए संसद की कार्यवाही का संदर्भ दिया जा सकता है और यदि आवश्यक हो, तो व्याख्या के उद्देश्य से क़ानून में कुछ शब्द जोड़े जा सकते हैं यह विधानमंडल की मंशा के अनुरूप है।

(25) कर क़ानून और व्याख्या के नियमों के दायरे, उद्देश्य और वस्तु के संदर्भ में, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, आइए अब हम याचिकाकर्ताओं की प्रस्तुतियों को उपरोक्त कानूनी प्रस्तावों की कसौटी पर परखते हैं। यह जोरदार तर्क दिया गया है कि अधिनियम की धारा 9 याचिकाकर्ताओं को खरीद कर के भुगतान से छूट देती है। प्रतिवादी इसकी वसूली के लिए कार्रवाई शुर नहीं कर सके।

(26) याचिकाकर्ताओं ने देश से बाहर निर्यात किए जाने वाले भूसे के प्रयोजन के लिए खरीदे गए धान पर अधिनियम की धारा 9 द्वारा दी गई अंतर्निहित छूट की दलील पर खरीद कर के भुगतान से छूट का दावा किया है। उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में *होटल बालाज के मामले (* सुप्रा) *मुरली मनोहर के* ***मामले***

(सुप्रा) और *जगजीत शुगर मिल के मामले (सुप्रा)* में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भरोसा किया है । वास्तव में यह प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त धारा को सबसे पहले 15 अक्टूबर, 1990 के अध्यादेश संख्या 2 द्वारा हटा दिया गया था। 1990 और उसके बाद 1991 के अधिनियम संख्या 4, दिनांक 16 अप्रैल, 1991 द्वारा, धारा 6 में तदनुरूपी और प्रभावी संशोधन करके

अधिनियम की धारा 15-ए. यह तर्क दिया गया है कि अध्यादेश और संशोधन अधिनियम की एक संयुक्त रीडिंग ने स्पष्ट रूप से सुझाव दिया है कि धारा 9 की चूक और चार्जिंग सेक्शन टीजे और 15-ए के संशोधन के बाद, कर का भुगतान करने के लिए निर्धारिती की देनदारी पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी रखी गई थी ।

(27) प्रतिवादियों के विद्वान वकील की इस दलील में दम है क्योंकि 1991 के अधिनियम संख्या 4 द्वारा धारा 9 को हटाने के बाद, अधिनियम की धारा 6 और 15-ए के प्रावधानों को पूर्वव्यापी रूप से लागू किया गया है। 27 मई, 1971 से प्रभावी। धारा 9 की अनुपस्थिति में और अधिनियम की धारा 6 और 15-ए में संशोधन के बाद 27 मई, 1971 से याचिकाकर्ताओं जैसे व्यक्तियों पर पूर्वव्यापी प्रभाव से कर दायित्व लगाया गया है। इसलिए, यह देखा जाना चाहिए कि क्या, सबसे पहले 1990 के अध्यादेश संख्या 2 और उसके बाद 1991 के अधिनियम संख्या 4 द्वारा धारा 9 के कारण उत्पन्न हुए संदेह, यदि कोई हो, को दूर करने के बाद पूर्वव्यापी रूप से कर दायित्व लगाया जा सकता है। अधिनियम का. याचिकाकर्ताओं के अनुसार यह विधायिका की क्षमता के भीतर नहीं था, जबकि उत्तरदाताओं ने दलील दी है कि यदि विधायिका के पास इस विषय पर कानून बनाने की विधायी क्षमता है, तो प्रावधान को निरस्त करने और पूर्वव्यापी रूप से कर दायित्व लगाने पर कोई रोक नहीं है।

(28) यह कानून की स्वीकृत स्थिति है कि विधानमंडल के पास उन्हें सौंपे गए विधायिका के क्षेत्र के भीतर कानून बनाने की पूर्ण शक्तियां हैं, लेकिन संविधान के भाग 11 में निर्दिष्ट कुछ संवैधानिक प्रतिबंधों के अधीन हैं। माना जाता है कि विधायिका के पास संभावित और पूर्वव्यापी रूप से कानून बनाने की शक्ति है।

(29) *जे.के. जूट मिल्स कंपनी लिमिटेड* बनाम *उत्तर प्रदेश राज्य (8)* में सर्वोच्च न्यायालय ने इस संदर्भ में विधानमंडल की शक्ति की जांच की और कहा:

> "किसी विधायिका को उसे सौंपे गए विषय के संदर्भ में कानून बनाने की शक्ति है। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, अयोग्य केवल संविधान द्वारा लगाई गई किसी भी सीमा के अधीन है। ऐसी शक्ति के प्रयोग में, विधायिका एक ऐसा अधिनियम बनाने के लिए सक्षम होगी, जो या तो संभावित या पूर्वव्यापी हो। *भारत संघ* बनाम *मदन गोपाल,* 1954

में

(6) एआईआर 1961 एससी 1534,

हरियाणा और अन्य (आईटी. पी. सेठी, जे.) एससीआईटी 541, जैसा कि टिप्स कोर्ट ने माना था कि संविधान की अनुसूची VII में लिस (I) की प्रविष्टि 82 के तहत आय पर कर लगाने की शक्ति, एक अवधि के लिए पूर्वव्यापी संचालन के साथ आयकर लगाने की शक्ति को समझती है। संविधान के अनुसार। वस्तुओं की बिक्री पर कर लगाने वाले कानूनों के संबंध में स्थिति वही होगी। एमपीवी *सुंदररामियर* एंड कंपनी बनाम *आंध्र प्रदेश राज्य,* 1958 एससीआर 144 में, इस न्यायालय को अधिनियमित कानून की वैधता पर विचार करने का अवसर मिला था। संसद द्वारा अंतर-राज्यीय व्यापार के दौरान कुछ बिक्री पर कर लगाने वाले राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित कानूनों को पूर्वव्यापी प्रभाव देते हुए। इस कानून की वैधता के खिलाफ उठाए गए विवादों में से एक यह था कि कला की शर्तों को ध्यान में रखते हुए। 286(2) पूर्वव्यापी कानून संसद के दायरे में नहीं था। इस तर्क को खारिज करते हुए, न्यायालय ने कहा: -

> "अनुच्छेद 286(2) केवल यह प्रावधान करता है कि किसी राज्य का कोई भी कानून अंतर-राज्यीय बिक्री पर कर नहीं लगाएगा, सिवाय इसके कि जहां तक संसद लागू हो) - अन्यथा प्रदान करें। यह संसद द्वारा पारित किये जाने वाले कानून की प्रकृति पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है। ' दूसरी ओर, ये शब्द अब तक स्पष्ट रूप से संसद पर छोड़ देते हैं कि वह अपने द्वारा अधिनियमित किए जाने वाले कानून के स्वरूप और प्रकृति पर निर्णय ले। मटेरिया क्या है] देखने के लिए यह है कि अनुच्छेद 286(2) के तहत संसद को प्रदत्त शक्ति एक विधायी शक्ति है, और एक संप्रभु विधायिका को प्रदत्त ऐसी शक्ति अपने साथ किसी कानून को संभावित या पूर्वव्यापी रूप से अधिनियमित करने का अधिकार रखती है, जब तक कि ऐसा न किया जा सके । संविधान में ही उस शक्ति पर एक सीमा पाई जाएगी।"

और यह माना गया क कानून विधायिका की क्षमता के अधीन था। इसलिए हमें यह मानना चाहिए कि मान्यता अधिनियम प्रविष्टि 54 के तहत विधायिका की शक्तियों का *उल्लंघन नहीं करता है, इस कारण से कि यह पूर्वव्यापी रूप से संचालित होता है।*

(30) *युनाइटेड vप्रोविंसेसआई* बनाम *माउंट एस्टिगाउबे और अन्य* (8ए) में संघीय अदालत ने कहा था: -

"उनके अपने क्षेत्र में भारतीय विधायिकाओं की शक्तियां उतनी ही बड़ी और प्रचुर हैं जितनी स्वयं संसद की, और यह प्रदान करने का भार कि वे पूर्वव्यापी कानून के खिलाफ एक अजीब और असामान्य निषेध के अधीन हैं, निश्चित रूप से उन लोगों पर होना चाहिए जो इस पर जोर देते हैं। . धारा 292 की भाषा में ऐसा कुछ भी नहीं है जो संसद की ओर से उन्हें (भारतीय विधानमंडलों को) उस निषेध के अधीन बनाने के किसी इरादे का सुझाव देता हो, न ही, इतना घिनौना, जितना प्रासंगिक हो, कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि संसद को ऐसा क्यों करना चाहिए था इसलिए"।

v31) *पियारे दुसाध और अन्य* बनाम *सम्राट* (9), *सुबली और अन्य* बनाम *अटॉर्नी जनरल* (10), और *वेस्टर्न ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड में भी इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया गया था। लिमिटेड* बनाम *क्रॉप* (11) *राय रामकृष्ण* बनाम *राज्य ओज बिहार (12)* में , पूर्वव्यापी रूप से कानून बनाने की विधानमंडल की शक्ति पर विचार किया गया और यह माना गया:

तीन सूचियों में कई प्रविष्टियों द्वारा कवर किए गए विषयों के संबंध में कानून बनाने के लिए उपयुक्त विधायिकाओं को प्रदत्त विधायी शक्तियों का प्रयोग संभावित और पूर्वव्यापी दोनों तरह से किया जा सकता है। जहां विधायिका एक वैध कानून बना सकती है, वह न केवल उक्त कानून के भौतिक प्रावधानों के संभावित संचालन के लिए प्रदान कर सकती है, बल्कि यह उक्त प्रावधानों के पूर्वव्यापी संचालन के लिए भी प्रदान कर सकती है। इसी प्रकार, इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रश्न में विधायी शक्ति में उन कानूनों को मान्य करने की सहायक या सहायक शक्ति शामिल है जो अमान्य पाए गए हैं। यदि किसी विधायिका द्वारा पारित किसी कानून को न्यायालयों द्वारा एक या किसी अन्य बीमारी के कारण अमान्य करार दिया जाता है, तो यह उपयुक्त विधायिका को उक्त कमजोरी को ठीक करने और एक वैध कानून पारित करने के लिए सक्षम होगा ताकि उक्त प्रावधानों को लागू किया जा सके। पहले का कानून पारित होने की तारीख से प्रभावी होता है।

(33) हालाँकि, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्रत्येक क़ानून को प्रथम *दृष्टया* संभावित माना जाता है जब तक कि यह स्पष्ट रूप से या आवश्यक रूप से पूर्वव्यापी संचालन के लिए आवश्यक निहितार्थ न हो। यदि क़ानून में शब्द विधायिका की मंशा दिखाने के लिए पर्याप्त हैं, तो न्यायालयों द्वारा अन्यथा कोई अन्य अर्थ नहीं दिया जा सकता है।

(34) *जवाहरमल* बनाम *राजस्थान राज्य (13)* में , सर्वोच्च न्यायालय ने स्थिति को दोहराया और निम्नानुसार कहा: -

> "यह अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है कि कानून बनाने की शक्ति में संभावित रूप से, साथ ही पूर्वव्यापी रूप से कानून बनाने की शक्ति शामिल है, और इस संबंध में, कर कानून किसी भी अन्य कानून से अलग नहीं है। यदि विधानमंडल ने कोई कर लगाने का निर्णय लिया है, तो वह ऐसा कर या तो संभावित रूप से या यहां तक कि पूर्वव्यापी रूप से भी लगा सकता है । जब कर लगाने के लिए पूर्वव्यापी कानून पारित किया जाता है, तो संभावित मामलों में, यह विचार करना आवश्यक हो जाता है कि क्या ऐसा पूर्वव्यापी कराधान उचित है या नहीं। लेकिन मामले के इस सैद्धांतिक पहलू के अलावा, कर लगाने की शक्ति का प्रयोग विधायिका द्वारा संभावित या पूर्वव्यापी रूप से पूरी तरह से किया जा सकता है ।

(35) यदि किसी संशोधित क़ानून का उद्देश्य वाक्यांशविज्ञान में दोष या अन्य प्रकृति की कमी को दूर करना और सुधारना है और पहले के अधिनियम के तहत कार्यवाही को वैध बनाना है, भले ही न्यायालय ने कुछ दुर्बलताओं के कारण इसे दूषित पाया हो, तो ऐसा संशोधन और वैधीकरण अधिनियम प्रभावी होगा। और संक्षेप मे पूर्वव्यापी संचालन का उद्देश्य उस उद्देश्य को प्रभावित करना और क्रियान्वित करना है जिसके लिए पहले के प्रमुख अधिनियम में संशोधन और संशोधन किया गया था। ऐसा संशोधन और वैधीकरण अधिनियम जिसका उद्देश्य "छोटी मरम्मत" करना है, कानून का एक स्वीकार्य तरीका है और वित्तीय अधिनियमों में अक्सर इसका सहारा लिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने *'कृष्णमूर्ति* एंड कंपनी बनाम *मद्रास राज्य (14) में, 'सहायक शहरी भूमि कर आयुक्त** बनाम *बकिंघम एंड कर्नाटक कंपनी लिमिटेड (15)* में अपने पहले के फैसले को दोहराया

और अनुमोदित किया , जिसमें निर्भरता 73 हार्वर्ड लॉ रिव्यू 692 में पृष्ठ 705 पर निम्नलिखित अनुच्छेद पर रखा गया था: -

> "यह आवश्यक है कि विधायिका क़ानूनों या उनके प्रशासन में विज्ञापन संबंधी दोषों को ठीक करने में सक्षम हो, जिसे उपयुक्त रूप से 'छोटी मरम्मत' कहा जाता है। इसके अलावा, जो व्यक्ति यह दावा करता है कि निहित अधिकार विलोपन से उत्पन्न हुआ है, वह अप्रत्याशित लाभ की तलाश कर रहा है क्योंकि विधायिका या प्रशासक की कार्रवाई का वह प्रभाव होता जिसके लिए वह इरादा था और हो सकता था, तो ऐसा कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार, सरकार के प्रशासन में इस तरह के दोष को पूर्वव्यापी रूप से ठीक करने में रुचि दोष से लाभ उठाने में व्यक्ति के हित को महत्व देती है... न्यायालय ''पूर्वव्यापी कराधान'' की आवश्यकता के रूप में विधायी निर्णय को खारिज करने के लिए बेहद अनिच्छुक रहा है। , न केवल पर्याप्त राजस्व प्राप्त करने में सर्वोपरि सरकारी हित के कारण, बल्कि इसलिए भी क्योंकि कर किसी दंड या संविदात्मक दायित्व की प्रकृति में नहीं हैं, बल्कि उन लोगों के बीच सरकार की लागत को विभाजित करने का एक साधन है जो इससे लाभान्वित होते हैं ।

(36) एस इन बनाम *शिव दत्त राज*ए *फतेह* इर *चंद* बनाम यूनियन ऑफ़िक *इंडिया* , सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 9 के दायरे पर विचार किया जिसके द्वारा पूर्वव्यापी रूप से जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया था *और* यह माना गया कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 या 20 का उल्लंघन नहीं था। यह घोषित किया गया था:

> "हमने पहले ही उन परिस्थितियों का संकेत दिया है जिनके तहत पूर्वव्यापी प्रभाव से जुर्माना लगाना और जुर्माना लगाने और उसकी वसूली से संबंधित सभी कार्यवाहियों को मान्य करना आवश्यक हो गया है। कर या शुल्क लगाने को पूर्वव्यापी रूप से मान्य करने वाला कानून बनाने की विधायिका की शक्ति के दायरे पर इस न्यायालय ने छोटाभाई जेठाभाई पटेल एंड कंपनी बनाम भारत संघ, एआईआर 1962 एससी 1006 मामले में विचार किया था। न्यायालय *ने* माना *कि* संसद 'अपने

विधायी क्षेत्र के भीतर कार्य करने की शक्ति थी और वह कानून द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम के तहत संभावित और पूर्वव्यापी दोनों तरह से उत्पाद शुल्क लगा सकता था। 1944 में भी यह स्थापित किया गया था कि कानून को दिए गए पूर्वव्यापी प्रभाव के कारण, निर्धारिती खरीदारों को उत्पाद शुल्क देने में असमर्थ था। कुछ अमेरिकी निर्णयों पर विचार करने के बाद, अव्यंगार, टी. पृष्ठ 37 (एससीआर के) पर देखा गया; (एआईआर के पृ. 1022-23 पर) **इस प्रकार:**

"इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका या अमेरिका के संविधान के तहत भी असंवैधानिक रूप से पूर्वव्यापी कर को "बीवें संशोधन की अस्पष्ट रूपरेखा" कहा गया है, जबकि भारतीय संविधान के तहत यह आधार है संपत्ति के अधिकारों के उल्लंघन का परीक्षण "उचित प्रक्रिया" के लचीले नियम से नहीं, बल्कि अनुच्छेद 19(5) में निर्धारित अधिक सटीक मानदंडों पर किया जाता है। कर लगाने में केवल पूर्वव्यापीता अनुच्छेद 19(1) (एफ) के तहत संपत्ति रखने के अधिकार का उल्लंघन करने या कला के तहत संपत्ति से व्यक्ति को वंचित करने के आधार पर कानून को असंवैधानिक नहीं बना सकती है। 31(1). यदि एक ओर, विचाराधीन कर अधिनियम संघ या राज्य की विधायी क्षमता से परे था, तो आवश्यक रूप से विभिन्न विचार उत्पन्न होते हैं। इस तरह का अनधिकृत अधिरोपण निस्संदेह संपत्ति रखने के अधिकार पर एक उचित प्रतिबंध नहीं होगा, साथ ही व्यवसाय चलाने पर एक अनुचित प्रतिबंध भी होगा। यदि विचाराधीन कर वह है जो किसी व्यक्ति पर उसकी व्यावसायिक गतिविधि के संबंध में लगाया जाता है।"

राज रामकृष्ण बनाम *बिहार राज्य, एआईआर 1963 एससी 1667* मामले में न्यायालय भारत में पूर्वव्यापी कराधान कानून बनाने की कानून व्यवस्था की शक्ति के बारे में अधिक सशक्त था। यह माना गया कि यदि इसकी आवश्यक विशेषताओं में एक कर क़ानून विधायिका की क्षमता के भीतर है, तो इसे पूर्वव्यापी प्रभाव दिए जाने पर यह बंद नहीं होगा। इसलिए, कानून बनाने की शक्ति में इसके दायरे में सभी प्रासंगिक प्रावधान शामिल हैं जो इसके सहायक या आकस्मिक हैं। ब्याज लगाने और पूर्वव्यापी रूप से जुर्माना लगाने और उन कानूनों के तहत पहले की कार्यवाही को मान्य करने का प्रावधान, जिन्हें असंवैधानिकता के तत्व को हटाने के बाद असंवैधानिक घोषित किया गया है, विधायी शक्ति के दायरे में शामिल हैं। राय रामकृष्ण (सुप्रा) के उपर्युक्त मामले में 1950 में पारित यात्रियों और वस्तुओं पर कर लगाने वाले बिहार अधिनियम को इस न्यायालय द्वारा दिसंबर, 1960 में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। उक्त लेवी में

संवैधानिक कमियों को दूर करने के बाद उसे वैध बनाने वाला एक अधिनियम 23 सितंबर, 1961 को राष्ट्रपति की सहमति से पारित किया गया था और उस अधिनियम को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया था।

तारीख 1 अप्रैल, 1950 को पिछला अधिनियम, जिसे असंवैधानिक घोषित किया गया था, लागू हुआ था। वैधीकरण अधिनियम के खिलाफ सीमित चुनौती यह थी कि इसकी धारा 23 (बी) में निहित प्रावधान यह प्रदान करते हैं कि कर या दंड के रूप में किसी भी राशि के मूल्यांकन, संग्रह और वसूली के लिए कोई भी कार्यवाही शुरू की गई या शुरू की गई थी। पहले अधिनियम के प्रावधान जिन्हें असंवैधानिक घोषित किया गया था या 1 अप्रैल, 1950 से 31 जुलाई, 1961 की अवधि के दौरान उसके तहत बनाए गए नियम यानी उस तारीख तक, जिस दिन एक अध्यादेश जिसे प्रश्न में मान्य अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, लागू हुआ। , को मान्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार शुरू और संचालित माना जाना चाहिए और यदि पहले से ही पूरा नहीं हुआ है तो इसे जारी रखा जाना चाहिए और मान्य अधिनियम के अनुसार पूरा किया जाना चाहिए जो अनुच्छेद 304 (बी) और अनुच्छेद 19 (1) के विपरीत है। (एफ) और (जी)। उस मामले में सदरलैंड में 'क़ानून और वैधानिक निर्माण' पर की गई टिप्पणी के आधार पर यह आग्रह किया गया था कि: -

"यदि विधायिका स्पष्ट रूप से ऐसा चाहती है तो क़ानून पूर्वव्यापी हो सकते हैं। यदि किसी कानून की पूर्वव्यापी विशेषता मनमाना और बोझिल है तो क़ानून कायम नहीं रहेगा।

पूर्वव्यापी अवधि की अवधि, यानी ग्यारह वर्ष, कला के तहत गारंटीकृत अधिकारों पर एक अनुचित प्रतिबंध था। 19(1) (एफ) और (जी)। इस विवाद को इस न्यायालय ने पृष्ठ 915 और 916 (एससीआर के) पर खारिज कर दिया था; (एआईआर के पृष्ठ 1674 पर) रिपोर्ट इस प्रकार है:

"हमें नहीं लगता कि इस तरह के यांत्रिक परीक्षण को अधिनियम के पूर्वव्यापी संचालन की वैधता निर्धारित करने में लागू किया जा सकता है। यह कल्पना की जा सकती है कि ऐसे मामले सामन आ सकते हैं जिनमें किसी कर निर्धारण या अन्य क़ानून का पूर्वव्यापी संचालन अतार्किकता का ऐसा तत्व पेश कर सकता है कि लगाए गए प्रतिबंध असंवैधानिक के रूप में गंभीर चुनौती के लिए खुले होंगे: लेकिन कवर किए गए समय की लंबाई का परीक्षण रेट्रोस पेक्टिव ऑपरेशन

द्वारा स्वयं को निर्णायक परीक्षण नहीं किया जा सकता है। हमारे पास एक क़ानून हो सकता है जिसका पूर्वव्यापी प्रभाव तुलनात्मक रूप से कम हो

> अवधि और फिर भी यह संभव है कि इसके द्वारा लगाए गए प्रतिबंध की प्रकृति इस प्रकार की हो सकती है कि पूर्वव्यापी संचालन में गंभीर दुर्बलता उत्पन्न हो। दूसरी ओर, हमें ऐसे मामले मिल सकते हैं जहां क़ानून के पूर्वव्यापी संचालन द्वारा कवर की गई अवधि, हालांकि लंबी है, ऐसी कोई दुर्बलता नहीं लाएगी। एक वैध अधिनियम का मामला लीजिए। यदि विधायिका द्वारा पारित किसी क़ानून को अदालत के समक्ष कार्यवाही में चुनौती दी जाती है, और अंततः चुनौती बरकरार रहती है और क़ानून रद्द कर दिया जाता है, तो यह संभावना नहीं है कि न्यायिक कार्यवाही में काफी लंबा समय लग सकता है और विधायिका अच्छी तरह से निर्णय ले सकती है। पिछले अधिनियम में कथित कमजोरी को ठीक करने के लिए अपनी विधायी शक्ति का उपयोग करने से पहले उक्त कार्यवाही में अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा करें । ऐसे मामले में, यदि मामले में अंतिम न्यायिक फैसला सुनाए जाने के बाद विधायिका एक वैध अधिनियम पारित करती है, तो यह अदालत में न्यायिक कार्यवाही द्वारा ली गई लंबी अवधि को कवर कर सकता है और फिर भी इसे रोकना अनुचित होगा क्योंकि पूर्वव्यापी प्रभाव परिचालन में लंबी अवधि शामिल है, इसलिए, इसके द्वारा लगाया गया प्रतिबंध अनुचित है। इसीलिए हमारा मानना है कि रेट्रो के सक्रिय संचालन द्वारा तय की गई समयावधि का परीक्षण अपने आप में एक डी'आइसवे परीक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है।"

इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा अधिनियम की धारा 48 के दायरे पर भी विचार किया जिसके द्वारा जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया था और माना गया कि ऐसा प्रावधान, हालांकि पूर्वव्यापी रूप से बनाया गया था, संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता है।

(37) क़ानूनों की व्याख्या का यह भी प्रमुख सिद्धांत है कि न्यायालय को कानून की व्याख्या इस प्रकार करनी है कि वह शरारत को दबा सके और उपचार

को आगे बढ़ा सके और चोरी और शरारत की निरंतरता को दबा सके। किसी क़ानून के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, ऐसी व्याख्या दी जानी चाहिए जो वास्तव में अप्रत्यक्ष या घुमावदार तरीके से करने या न करने के सभी प्रयासों को विफल कर देती है जो निषिद्ध या आदेशित है। चोरी या दुरुपयोग को रोकने के लिए निर्माण से निपटने के दौरान क़ानून की व्याख्या पर मैक्सवेल कहते हैं: -

> "निर्माण के इस तरीके के दो पहलू हैं। एक यह है कि अदालतें, शरारत नियम को ध्यान में रखते हुए, किसी क़ानून की भाषा को सीमित करने में चतुर नहीं होंगी ताकि व्यक्तियों को अनुमति दी जा सके

इसके जाल से बचने के लिए इसके दायरे में। दूसरा यह है कि इस क़ानून को लेनदेन के उस रूप के बजाय पदार्थ पर लागू किया जा सकता है, इस प्रकार किसी भी बदलाव और युक्ति को हराया जा सकता है जो पार्टियों ने अधिनियम के बाहर होने की उम्मीद में तैयार की हो सकती है। जब न्यायालयों को छिपाने का कोई प्रयास मिलता है, तो वे, विल्मोट सीजे **के शब्दों में** , "मकड़ी के जाल को हटा देंगे, और लेन-देन को उनकी वास्तविक रोशनी में दिखा देंगे।"

(38) *राय राम कृष्ण* बनाम बिहार *राज्य (17)* में , सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने कहा था: -

"जहां विधायिका एक वैध कानून बना सकती है, वह न केवल उक्त कानून के भौतिक प्रावधानों के संभावित संचालन के लिए प्रदान कर सकती है, बल्कि यह उक्त प्रावधानों के पूर्वव्यापी संचालन के लिए भी प्रदान कर सकती है।"

(39) हाल के एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने *'एंटरटेनमेंट टैक्स ऑफिजिसर।* बनाम *अंबे पिक्चर पैलेस* (18) में कहा है: -

यूओआई बनाम *मदन* में इस न्यायालय के फैसले का संदर्भ लिया जा सकता है)। *गोपाल काबरा* (1954) 25 आईटीआर 58 (एससी)। फिर से *कृष्णमूर्ति एंड कंपनी* बनाम *मद्रास राज्य* (1973) 31 एसटीसी 190 में, इस न्यायालय ने माना है कि विषयों के संबंध में कानून बनाने के लिए विधायी शक्ति उपयुक्त विधानमंडलों को प्रदान की गई है। तीन सूचियों में कई प्रविष्टियों को संभावित और पूर्वव्यापी दोनों तरह से प्रयोग किया जा सकता है।

(40) *अध्यादेश* संख्या 2 के तहत, मूल अधिनियम की धारा 9 को हटा दिया गया था और धारा 15-ए को 27 मई, 1971 से प्रतिस्थापित किया गया था। अध्यादेश को 1991 के हरियाणा अधिनियम संख्या 4 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। इसका प्रभाव इसके बाद हुआ मूल अधिनियम की धारा 9 का लोप, संशोधित धारा 15 को 27 मई, 1971 से पूर्वव्यापी रूप से लागू किया गया था। अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के खंड (बी) में प्रावधान (iii) को अधिनियम संख्या

में शामिल किया गया था। अधिनियम की धारा 17 में प्रावधान है कि घोषित माल पर कर बिक्री या खरीद के स्तर पर लगाया जाएगा, जैसा भी मामला हो, और अनुसूची 'ईएच में ऐसे माल के खिलाफ निर्दिष्ट परिस्थितियों में माल प्रदान किया जाएगा। उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट बिक्री या खरीद के किसी भी चरण में कर के अधीन नहीं किया गया है। इस तरह के सामान की अंतिम खरीद के चरण में अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी डीलर द्वारा धान पर कर लगाया जाएगा और इसके अलावा उक्त धारा के तहत कर धारा 27 के तहत स्वीकार्य कटौती प्रदान करने के बाद लगाया, लगाया और भुगतान किया जाएगा। अधिनियम का. संशोधित धारा 15-ए जिसे 27 मई, 1071 से लागू किया गया है। निम्नानुसार है: -

"15-ए. कुछ मामलों में कर का समायोजन या रिफंड।—धारा 15 की उपधारा (1) के परंतुक के खंड (iii) के प्रावधानों के अधीन और शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, —

(i) इस अधिनियम या केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के तहत किसी डीलर द्वारा निर्मित माल की बिक्री पर लगाए जाने वाले कर को कर के अलावा माल की बिक्री या खरीद पर राज्य में भुगतान किए गए कर की राशि से कम किया जाएगा। उनक निर्माण में प्रयुक्त धान, कपास और तिलहन की अंतिम खरीद पर भुगतान; और

(ii) जब निर्मित वस्तुओं की बिक्री पर अनुसूची बी में निर्दिष्ट शर्तों और अपवादों के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाता है, या जब निर्मित वस्तुओं की बिक्री पर लगाया जाने वाला कर बिक्री पर राज्य में भुगतान किए गए कर से कम है या माल की खरीद, धान, कपास और तिलहन की अंतिम खरीद पर भुगतान किए गए कर के अलावा, उनके निर्माण में उपयोग किया जाता है, भुगतान किए गए कर की पूरी राशि या बिक्री पर लगाए गए कर पर भुगतान किए गए कर की अतिरिक्त राशि, जैसा भी मामला हो यदि निर्मित माल राज्य में या अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान, या भारत के क्षेत्र से बाहर निर्यात के दौरान बेचा जाता है, तो वापसी

योग्य हो सकता है:

बशर्ते कि यदि निर्मित माल 1 जनवरी, 1988 से पहले बेचा गया हो, तो उनके निर्माण में उपयोग किए गए, धारा 18 के तहत बिक्री के पहले चरण में कर के लिए लगाए जाने वाले माल पर भुगतान किया गया कर वापस नहीं किया जाएगा।

(41) अधिनियम की धारा 15-ए के प्रावधान विशेष रूप से उन कर योग्य वस्तुओं, व्यक्तियों और घटनाओं का उल्लेख करते हैं जो इस अनुभाग को चार्जिंग अनुभाग बनाते हैं। *आदर्श इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन* बनाम *हरियाणा राज्य (19)* में यह माना गया था कि चार्जिंग अनुभाग की आवश्यकताएं हैं: -

1. कि जिस वस्तु पर कर लगाया जाना है उसका उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए;

2. जिन परिस्थितियों में कर लगाया जाना है, उनका उल्लेख किया जाना चाहिए था; और

5. कर लगाने के चरण और कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को परिभाषित किया जाए।

(42) खरीद कर का भुगतान करने की देनदारी के संबंध में धारा 9 के माध्यम से, यदि कोई हो, उत्पन्न संदेह को अधिनियम की धारा 15-ए को प्रतिस्थापित करके और अधिनियम की धारा 6 और 15 में संबंधित संशोधन करके दूर करने का इरादा *था*। धारा 15 का प्रभाव यह है कि यदि कोई विशिष्ट छूट नहीं दी गई है तो डीलर के कर योग्य टर्नओवर पर खंड (ए) और (बी) की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट दरों पर कर लगाया जाएगा। माना जाता है कि, धारा 9, स्थानापन्न - टी धार 15-ए के लोप और धारा 15 के पूर्वव्यापी संशोधन के बाद याचिकाकर्ताओं के पक्ष में कोई विशिष्ट या निहित छूट अस्तित्व में नहीं है। इसलिए, कर का भुगतान करने का दायित्व धारा 15 के साथ धारा 6 द्वारा विनियमित है और समायोजन , यदि कोई हो, अधिनियम की धारा 15-ए के तहत स्वीकार्य है। याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम की धारा 15-ए के अर्थ में किसी भी समायोजन का दावा नहीं किया है और यह सही भी है क्योंकि वे निर्यात किए जाने वाले चावल की भूसी के प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले धान की खरीद पर प्रारंभिक कर के भुगतान से

छूट का दावा कर रहे हैं।

(43) क़ानून की व्याख्या के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कर लगाने का विधानमंडल का इरादा है! चावल के निर्यात के लिए उपयोग किए जाने वाले धान की खरीद पर इतनी अच्छी तरह से प्रदर्शन किया गया है कि प्रतिवादी-राज्य की ओर से उठाए गए विवाद को स्वीकार करने और याचिकाकर्ताओं को कर दायित्व के लिए उत्तरदायी ठहराने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक संख्या ॥-HLA/91 पेश करते हुए। 1973 में धारा 9 को हटाने और धारा 15-ए को प्रतिस्थापित करने के अलावा धारा 15 में संशोधन करने का प्रस्ताव। इसे उद्देश्य एवं कारण कथन में इस प्रकार बताया गया है:-

(19)79 एसटीसी 94.

"राज्य के भीतर से खरीदे गए माल के खरीद मूल्य पर एक कर, जब राज्य के बाहर शाखाओं में स्थानांतरित किया जाता है या खेप के आधार पर बिक्री के लिए भेजा जाता है या जब माल के निर्माण में उपयोग किया जाता है, और निर्मित माल या तो शाखाओं में स्थानांतरित किया जाता है या राज्य के बाहर खेप के आधार पर बिक्री के लिए भेजा गया, हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम की धारा 9 और धारा 24 के तहत लगाया गया था। हालाँकि *देस राज पुष्प कुमार गुलाटी बनाम* राज्य *मामले* में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने माना कि कर योग्य घटना माल की खरीद थी और धारा 9 वैध थी, फिर भी भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मैसर्स गुड ईयर इंडिया लिमिटेड मामले में , फ़रीदाबाद ने अन्य बातों *के साथ-साथ* माना है कि कर योग्य घटना माल का प्रेषण है न कि माल की खरीद और राज्य ऐसे प्रावधानों को लागू करने के लिए विधायी रूप से सक्षम नहीं है। दूसरे शब्दों में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *उपरोक्त अधिनियम की धारा 9(1)(बी) और धारा 24(3) के प्रावधानों को रद्द कर दिया।* सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बताई गई खामियों को दूर करने और किसी भी संदेह और अस्पष्टता को दूर करने के लिए, हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 में संशोधन किया गया, - 1990 के

अधिनियम संख्या 1 के माध्यम से, और बाद में 12 अक्टूबर, 1990 क एक अध्यादेश द्वारा / और करयोग्य घटना को माल की खरीद पर ही स्थानांतरित कर दिया गया। हालाँकि, एक अन्य निर्णय में, *मेसर्स मुरली मनोहर एंड कंपनी* बनाम *स्लेट ऑफ हरियाणा* के मामले में , सुर-रेम कोर्ट ने, अप्रभावी, माना है कि *संशोधन* अधिनियम के तहत किया गया था। 1990 का क्रमांक 1 अभी भी राज्य सरकार को कुछ निर्दिष्ट लेनदेन पर खरीद कर लगाने का अधिकार नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अधिनियम में दी गई टर्नओवर की परिभाषा और कर के भुगतान के बिना सामान खरीदने के अधिकार के प्रावधान खरीद कर लगाने की अनुमति नहीं देते ह क्योंकि खरीद के मूल्य को 'टर्नओवर' की परिभाषा में शामिल नहीं किया जा सकता है। धारा 2(पी) में, विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए; स्पष्टीकरण 2. चूंकि, राज्य विधानमंडल भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 54 के संदर्भ में खरीद कर लगाने के लिए कानून बनाने में सक्षम है, ताकि बताई गई कमियों को दूर किया जा सके। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *मैसर्स मुरली मनोहर एंड कंपनी* बनाम *हरियाणा राज्य* के मामले में , अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन करना आवश्यक है ताकि प्रस्तावित खरीद कर लगान के विधायी इरादे को पूरा किया जा सके। बिल में।"

वित्तीय ज्ञापन के विवरण में यह कहा गया था: -

"मैसर्स मुरली मनोहर एंड कंपनी *बनाम* हरियाणा *राज्य के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बताई गई हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 में कमियों को दूर करने के लिए,* इसमें संशोधन करना आवश्यक है अधिनियम के प्रावधान ताकि खरीद कर लगाने के विधायी इरादे को पूरा किया जा सके।

(44) ज्ञापन में 1990 के अध्यादेश क्रमांक 2 के प्रावधानों में संशोधन के कारणों की व्याख्या करते हुए कहा गया:-

"सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लेनदेन पर खरीद कर लगाने वाले हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम की धारा 9 और धारा 24 (3) के प्रावधानों को रद्द कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय में समीक्षा के लिए एक आवेदन

दायर किया गया था और साथ ही सरकार को कर एकत्र करना जारी रखने के लिए सशक्त बनाने के लिए 1990 के अधिनियम 1 के *माध्यम से अधिनियम में कुछ संशोधन किए गए थे।* सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा आवेदन खारिज किए जाने के बाद और 1990 के अधिनियम 1 द्वारा किए गए कुछ संशोधनों को चुनौती देने वाली उच्च न्यायालय में कुछ नई रिटों को देखते हुए, तत्काल प्रभाव से कुछ और संशोधन करना आवश्यक हो गया, जो हरियाणा सामान्य बिक्री कर (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1990 के माध्यम से किया गया था। यह मामला मैसर्स *मुरली मनोहर* बनाम *हरियाणा राज्य के* मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आगे जांच के दायरे में आ गया है और इसे प्राप्त करने के लिए कुछ और संशोधन आवश्यक हो गए हैं। सरकार का उद्देश्य कुछ लेनदेन पर खरीद कर लगाना और एकत्र करना है। प्रस्तावित विधेयक में उपरोक्त सभी मामलों को व्यापक रूप से शामिल किया गया है और विधेयक को पूर्वव्यापी प्रभाव देने का प्रस्ताव है। इसलिए हरियाणा सामान्य बिक्री कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1990 को निरस्त करने का प्रस्ताव है। अध्यादेश और विधेयक के प्रावधानों में संशोधन बदली हुई परिस्थितियों को देखते हुए किया जाना है। इसके अलावा, लक्ष्यों को हासिल करना समय की मांग थी।

(45) 1990 के अध्यादेश संख्या 2 के प्रावधानों में संशोधन के कारणों की व्याख्या करने वाले उद्देश्यों और कारणों के विवरण, वित्तीय ज्ञापन और ज्ञापन के विवरण का अवलोकन, स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विधानमंडल का इरादा कर देनदारी से बचने और लगाए जाने से रोकने के लिए खामियों को दूर करना था । खरीद कर का: *मुरली मनोहर के मामले* में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद (सुप्रा)।

(46) राज्य अधिनियम को अधिनियमित करने और संशोधित करने की राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता को वास्तव में स्वीकार कर लिया गया है। अन्यथा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 286, प्रविष्टि 54, 7वीं अनुसूची की सूची II के साथ पठित अनुच्छेद 246 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, राज्य विधानमंडल को पैडव पर बिक्री और खरीद कर लगाने के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। न तो विवाद किया जा सकता है और न ही इनकार किया जा सकता है।

(47) याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने व्यर्थ ही यह आग्रह

करने का प्रयास किया कि अधिनियम की धारा 15-ए के संशोधित प्रावधान भेदभावपूर्ण होने के कारण असंवैधानिक हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि समान रूप से स्थित व्यक्तियों ने बीयर के साथ अलग व्यवहार किया है और चावल के निर्यात से निपटने वाले डीलरों पर धान की खरीद पर कर का भुगतान करने के दायित्व का बोझ नहीं डाला जा सकता है। यह भी तर्क दिया गया कि राज्य को अपनी इच्छानुसार कर और कर की दर लगाने की अनियंत्रित और नियंत्रणहीन शक्तियां प्रदान की गई हैं।

(48) अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि समानता के सिद्धांत का अर्थ यह नहीं निकाला जा सकता है कि प्रत्येक कानून का उन सभी व्यक्तियों के लिए सार्वभौमिक अनुप्रयोग होना चाहिए जो स्वभाव, उपलब्धि या परिस्थितियों से एक ही स्थिति में नहीं हैं। यह सिद्धांत वैध उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों को वर्गीकृत करने की शक्ति राज्य से छीन लेता है। विभेदक व्यवहार अपने आप में अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है /यदि कानून समान स्थिति वाले या अच्छी तरह से परिभाषित वर्ग के सदस्यों के साथ समान व्यवहार करता है तो इसे अप्रिय नहीं माना जा सकता है। यह विधानमंडल को निर्धारित करना है कि वह किन श्रेणियों को मुख्य कानून के दायरे में शामिल करना चाहता है और केवल इसलिए कि कुछ श्रेणियों को छोड़ दिया गया है, इससे विधान संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं होगा।

(49) *ईस्ट इंडिया टोबैको कंपनी* बनाम *आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य (20)* मामले में यह कहा गया था कि कानून के तहत बोझ उन व्यक्तियों पर पड़ता है जो कानून को भेदभावपूर्ण बताते हुए चुनौती देते हैं, जिन्हें यह स्थापित करना आवश्यक है कि यह प्रावधान किसी पर आधारित नहीं है। वैध वर्गीकरण. कराधान कानून में, "यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि राज्य के पास उन व्यक्तियों या वस्तुओं का चयन करने में व्यापक विवेक है जिन पर वह कर लगाएगा, और एक क़ानून इस आधार पर हमला करने के लिए खुला नहीं है कि वह कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं पर कर लगाता है और अन्य नहीं. यह है

(20) एआईआर 1962 एससी 1733।

केवल तभी जब इसके चयन की सीमा के भीतर, कानून समान रूप से संचालित होता है, और इसे किसी वैध वर्गीकरण के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है , कि यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। किसी चीज़ पर कर लगाने के लिए राज्य को हर चीज़ पर कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। कर निर्धारण क़ानून के तहत विधानमंडल के पास वर्गीकृत करने की व्यापक शक्तियाँ हैं और कर लगाए जाने वाले विषयों के संबंध में कार्य विवरण और कर की दर तय करने की शक्ति है, जो बदले में विधानमंडल द्वारा पहचाने जाने वाले सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक विचारों पर निर्भर करती है, और हो सकती है। सरकार पर छोड़ देने का विकल्प चुना। इसी प्रकार कर निर्धारण क़ानून द्वारा निर्धारित कर की दर की अधिकतम सीमा स्वयं इसे असंवैधानिकता के हमले से बचाने के लिए सामाजिक दिशानिर्देश प्रदान कर सकती है ।

जे

(50) *दिल्ली नगर निगम* बनाम *बिड़ला कॉटन , स्पिनिंग और वीविंग मिल्स (21)* मामले में , सुप्रीम कोर्ट ने माना कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 150 द्वारा निगम को अधिकतम दरें निर्धारित करके कोई भी वैकल्पिक कर लगाने की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। लगाए जाने वाले कर का ; व्यक्तियों के वर्ग या वर्ग या कर लगाए जाने वाली वस्तुओं और संपत्तियों का विवरण या विवरण तय करना और मूल्यांकन की प्रणाली निर्धारित करना और यदि कोई छूट दी जानी है, तो यह दिशाहीन नहीं है और इसे अत्यधिक प्रत्यायोजन के बराबर नहीं कहा जा सकता है।

(51) इसी आशय का *ग्लेशियर कोल्ड स्टोरेज और आइस मिल्स और अन्य* बनाम *मूल्यांकन प्राधिकरण*(22) मामले में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ का निर्णय है।

^52) ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने आधे-अधूरे मन से कथित अपमानजनक धाराओं की शक्तियों को असंवैधानिक होने की चुनौती दी है और किसी भी बुराई का उल्लेख नहीं किया है जो हमें इस धारा को अधिकारातीत घोषित करने के लिए प्रेरित कर सके /

(53) 3 उत्तरदाताओं के लिए वकील ने सबमिट किया है और हम इस बात से सहमत हैं कि क़ानून द्वारा अपेक्षित छूट विशिष्ट और स्पष्ट होनी चाहिए। ऐसी

छूट का अनुमान भी लगाया जा सकता है, बशर्ते ऐसा निष्कर्ष निकालने के लिए मजबूत और ठोस कारण हों। जहां क़ानून विशेष रूप से छूट से संबंधित है , किसी को भी धारा की भाषा को फैलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है

(21) एआईआर 1968 एससी 1232।

(22) 24 एसटीसी 426.

जो छूट का अनुमान लगाने के लिए पंक्तियों के बीच में पढ़कर इसके साथ हिंसा करने के समान हो सकता है। अधिनियम में, कानून की मंशा जहां भी वांछित हो, छूट देने की शक्ति विशेष रूप से धारा 13, 13-ए और 13-बी में बताई गई है। धारा 14 यह साबित करने का भार प्रदान करती है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रिंसिपल, एजेंट या किसी अन्य क्षमता में की गई कोई भी खरीद, बिक्री, आयात या निर्यात इस अधिनियम के तहत कर के लिए उत्तरदायी नहीं है, ऐसे व्यक्तियों पर होना चाहिए। याचिकाकर्ता वर्तमान मामले में सबूत के ऐसे बोझ का निर्वहन करने में बुरी तरह विफल रहे हैं,

(54) इसलिए, यह माना जाता है कि राज्य विधानमंडल 1991 के अधिनियम संख्या 4 को वैध रूप से कानून बनाने के लिए सहमत था, जिसके द्वारा धारा 0 और 15 में संबंधित संशोधन करके और एक नया प्रतिस्थापन करके अधिनियम की धारा 9 को हटा दिया गया था । धारा 15-ए. राज्य विधानमंडल देश से बाहर निर्यात किए जाने वाले चावल के निर्माण के उद्देश्य से उपयोग किए जाने वाले धान की खरीद के संबंध में याचिकाकर्ताओं पर कर दायित्व लगाकर इन प्रावधानों को पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी करने के लिए भी सक्षम था । प्रावधानों को खामियों को दूर करने और यदि कोई हो तो संदेह को दूर करने के घोषित इरादे से अधिनियमित किया गया था, जो कि विधानमंडल द्वारा संदर्भित सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के कारण याचिकाकर्ताओं की कर देयता के संबंध में उत्पन्न हुआ था। इसलिए, प्रतिवादी-उप उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त को मूल्यांकन आदेश में संशोधन के लिए मामले में *स्वत: कार्रवाई* करने का प्रस्ताव करते हुए राज्य अधिनियम की धारा 40 के तहत नोटिस जारी करना उचित था।

(55) यह विवादित नहीं है) पहले कहा गया था कि धान और चावल केंद्रीय अधिनियम की धारा 14 के तहत 1 डी एड सामान हैं और हरियाणा अधिनियम की धारा 15-ए और 17 के साथ पठित धारा 6 के तहत कर के अधीन दो अलग-अलग वस्तुएं हैं।

(56) मान लीजिए कि बट स्वीकार नहीं कर रहा: वह; यह संशोधन , 1991 के अधिनियम संख्या 4 और 1993 के अधिनियम संख्या 9 के तहत पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं किया गया था और मूल अधिनियम की धारा 9 को वैध रूप से छोड़ा नहीं गया है, याचिकाकर्ता का दावा जैसा कि अदालत में पेश किया गया है,

नहीं किया जा सकता है। उस स्थिति में भी स्वीकार किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने पक्ष में पेश की गई मुख्य बात यह है कि वे अधिनियम की धारा 9 के तहत छूट के हकदार हैं, जो उनके अनुसार शुल्क लगाने के साथ-साथ छूट देने वाला प्रावधान भी है। अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हुए, याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की नींव पर अपना महल बनाने की कोशिश की है।

'*होटल बालाजी और अन्य* बनाम *आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य* (23) और *जकाजीत। चीनी मिल का मामला* (सुप्रा) (24)।

(57) याचिकाकर्ताओं की ओर से की गई दलीलों की सराहना करने के लिए, चार्ज करने की धारा की मुख्य विशेषताओं और छूट को विनियमित करने वाले सिद्धांतों की जांच करना आवश्यक है।

(58) चार्जिंग अनुभाग की मुख्य विशेषताएं हैं: -

(a) जिस वस्तु पर कर लगाया जाना है, उसे निर्दिष्ट किया जाना चाहिए:

(b) जिन परिस्थितियों में कर लगाया जाना आवश्यक है, उनका उल्लेख किया जाना चाहिए; और

(c) कर लगाने का चरण और कर चुकाने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को परिभाषित किया गया होगा।

छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए, ध्यान में रखा जाने वाला सिद्धांत यह है कि दावा की गई छूट को विशिष्ट दिखाया जाना चाहिए और निहितार्थ स अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए जब तक कि ऐसा निहितार्थ अंतर्निहित न हो और इसमें कोई संदेह न हो।

(59) राज्य अधिनियम की धारा 9 की सुनवाई, "खरीद कर का भुगतान करने का दायित्व" है। . इस धारा को पहले 1976 के संशोधन अधिनियम संख्या 44 द्वारा और फिर 1979 के अधिनियम संख्या 11 द्वारा संशोधित किया गया था। 1983, 1984 का 11, 1986 का 8, 1986 का 16 और 1988 का 1। यह धारा वास्तव में 1990 के अध्यादेश संख्या 2 और उसके बाद 1991 के अधिनियम संख्या 4 द्वारा हटा दी गई थी। इन सभी अवधियों के लिए, उक्त धारा चालू रही क़ानून की किताब और उसका शीर्षक वही रहेगा जो प्रारंभिक अधिनियम में शामिल किया गया था।

(60) के लिए प्रासंगिक अवधि! इस रिट याचिका और अन्य समान रिट याचिकाओं का निर्णय 1982 से 1990 तक है। निर्णय और व्याख्या के प्रयोजनों के लिए, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तथ्यों की दलील निर्विवाद हैं: 'राज्य की धारा 9 के प्रासंगिक प्रावधान अधिनियम पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

"वस्तुओं के खरीद मूल्य पर कर का भुगतान करने का दायित्व।

(1) जहां एक डीलर इस अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है-

(ए) राज्य में एएचवी स्रोत से अनुसूची बी में निर्दिष्ट वस्तुओं के अलावा अन्य सामान खरीदता है और उनका उपयोग करता है।

(23) एएलके 1993 एससी एलओएलएच।

(24) 96 एसटीसी 344.

अनुसूची बी में निर्दिष्ट वस्तुओं के निर्माण में राज्य; या

(b) राज्य में स्रोत से अनुसूची बी में निर्दिष्ट वस्तुओं के अलावा अन्य सामान खरीदता है और उन्हें राज्य में किसी अन्य सामान के निर्माण में उपयोग करता है और या तो राज्य में बिक्री या प्रेषण के अलावा किसी अन्य तरीके से निर्मित सामान का निपटान करता है। अंतर्राज्यीय व्यापार पर या अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य में बिक्री के माध्यम से या अर्थ क भीतर भारत के क्षेत्र के बाहर निर्यात के दौरान निर्मित वस्तुओं को राज्य के बाहर किसी भी तरीके से भेजा जाता है। केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 5;

(c) राज्य में किसी भी स्रोत से अनुसूची बी में निर्दिष्ट वस्तुओं के अलावा अन्य सामान खरीदता है और उनका निर्यात करता है,

जिन परिस्थितियों में इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के तहत कोई कर देय नहीं है, धारा 17 के प्रावधानों के अधीन, ऐसे सामानों की खरीद पर धारा 15 के तहत अधिसूचित दरों पर कर लगाया जाएगा।

(61) बीमार। ओ में। चावल के निर्यात के प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने

वाले धान पर खरीद कर के भुगतान से छूट प्रदान करने वाले धारा के संबंध में तर्क की सराहना करते हुए धारा 6, 9, 15, 15-ए और 17 का भी संदर्भ देना आवश्यक है। धारा 6 राज्य अधिनियम कराधान की घटनाओं से संबंधित है और प्रावधान करता है कि प्रत्येक डीलर जिसका धार के प्रावधानों के लागू होने से ठीक पहले वर्ष के दौरान सकल कारोबार, कर योग्य मात्रा से अधिक हो गया है, सभी बिक्री पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और धारा के प्रावधानों के लागू होने के बाद खरीद प्रभावित हुई। एक डीलर ऐसे/कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है यदि वह अनुसूची 'बी' में निर्दिष्ट वस्तुओं का अतिरिक्त व्यापार करता है। यह धारा कर भुगतान की मात्रा, चरण और विधि भी प्रदान करती है। अधिनियम की धारा ॥ निम्नानुसार कर की दर प्रदान करती है: -

(a) शराब के मामले में एक रुपये में बीस पैसे (अनुसूची ए के क्रम संख्या 25 पर निर्दिष्ट विदेशी शराब और भारतीय निर्मित विदेशी तरल-जे और उसमें निर्दिष्ट अन्य वस्तुओं के मामले में एक रुपये में (बारह पैसे); और

(b) अन्य वस्तुओं के मामले में एक रुपये में आठ पैसे; जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्देशित कर सकती है।

(62) अधिनियम की धारा 15-ए करों के समायोजन और रिफंड से संबंधित है। अधिनियम की धारा 17 प्रदान करती है:

"घोषित माल पर कर.-घोषित माल पर कर बिक्री या खरीद के चरण में, जैसा भी मामला हो, लगाया जाएगा और देय होगा, और अनुसूची डी में ऐसे माल निर्दिष्ट परिस्थितियों के तहत;

बशर्ते कि जहां सामान अनुसूची डी में निर्दिष्ट बिक्री या खरीद के किसी भी चरण में कर के अधीन किया गया है, कर उस व्यापारी द्वारा लगाया या भुगतान किया जाएगा जो उसके द्वारा ऐसे सामान की अंतिम खरीद पर इस अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। :

बशर्ते कि इस धारा के तहत कर इस अधिनियम की धारा 27 के तहत स्वीकार्य कटौती प्रदान करने के बाद लगाया, लगाया और भुगतान

किया जाएगा।

(63) राज्य अधिनियम की धारा 9 का अवलोकन स्पष्ट रूप से कर योग्य घटनाओं, कर योग्य वस्तुओं, जिन व्यक्तियों से कर वसूल किया जाना है, को निर्दिष्ट करते हुए एक चार्जिंग धारा की सामग्री के अस्तित्व को इंगित करता है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने इन शब्दों का लाभ उठाने की कोशिश की है, "राज्य में बिक्री के अलावा या अंतर-राज्य में बिक्री के अलावा किसी भी तरीके से निर्मित माल को राज्य के बाहर किसी स्थान पर भेजना।" व्यापार या वाणिज्य या भारत के क्षेत्र के बाहर निर्यात के दौरान..." यह आग्रह करने के लिए कि विधायिका भी छूट प्रदान करने का इरादा रखती है। 'अन्य' शब्द के शब्दकोषीय अर्थ वैकल्पिक, अलग, अलग या प्रश्न में समान नहीं हैं, अतिरिक्त रहते हैं और 'अन्यथा' शब्द का अर्थ है, "किसी अन्य तरीके या तरीके से, अन्य कारणों से, अन्य मामलों में, अन्य स्थितियों में।" और 'छूट' शब्द का अर्थ है, “छूट का कार्य, छूट प्राप्त होने की अवस्था; किसी भी प्रेषक, कर्तव्य, बोझ आदि से मुक्ति। छूट के संबंध में न्यायिक आदेश यह है कि इसे क़ानून द्वारा विशेष रूप से प्रदान किया जाना चाहिए और इसका कड़ाई से अर्थ लगाया जाना चाहिए। यह भी तय किया गया है कि यदि निर्धारिती अपने मामले को किसी दावा की गई छूट के भीतर लाना चाहता है तो वह दी गई छूट की भाषा के भीतर स्पष्ट रूप से मामला बनाने और स्थापित करने के लिए बाध्य है। यह भी उतना ही सत्य है कि कर से छूट यदि क़ानून द्वारा दी गई है तो दी जानी चाहिए

दायरे और आयाम को कम करें और विधायिका या प्रत्यायोजित प्राधिकारी द्वारा इच्छित सीमाओं को लागू करके इसे रोका नहीं जाना चाहिए। सीएसटी बनाम *त्रिलोकी नाथ एंड संस* (25), *जया एंड कंपनी* बनाम *स्टेट ऑफ तमिलनाडु (मैड)* (26), और *यूनियन ऑफ इंडिया* बनाम वुड *पेपर लिमिटेड* (27) देखें।

(64) *गुडइयर इंडिया लिमिटेड* बनाम *हरियाणा राज्य (28)* में , सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम की धारा 9(1)(बी) असंवैधानिक थी,

(65) *मुरली मनोहर एंड कंपनी* बनाम *हरियाणा राज्य (29)* में , यह कहा गया: -

> "हरियाणा जनरल सेल्स टैक्स एक्ट, 1973 की धारा 9(1) (बी) के संबंध में गुडइयर केस (1990) 76 एसटीसी 71 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जिसे असंवैधानिक घोषित किया गया था, वह केवल एक कर की उगाही थी जहां कच्चे माल की खरीद और उपयोग राज्य के अंदर तैयार माल के निर्माण के लिए किया जाता है, जिसे बाद में आसानी से और बिना किसी बिक्री के भेज दिया जाता है, बल्कि राज्य के बाहर भेज दिया जाता है। हालाँकि, धारा 9(1)(बी) की भाषा पर आने वाले दो अन्य परिणामों के बारे में कुछ भी असंवैधानिक नहीं है; एक व्यक्त और दूसरा निहित; एक राजस्व के पक्ष में और दूसरा निर्धारिती के पक्ष में, अर्थात, (1) यदि विनिर्मित वस्तुओं का निपटान राज्य में ही किया जाता है तो कच्चे माल की खरीद पर कर लगेगा। बिक्री करना; और (2) यदि निर्मित माल राज्य से भेजा जाता है तो कच्चे माल की खरीद पर कोई कर नहीं लगेगा (i) स्थानीय बिक्री, (ii) अंतर-राज्य बिक्री, या (iii) a निर्यात के दौरान बिक्री। धारा 9(1)(बी) के ये दो पहलू गुड ईयर मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी जीवित हैं।

(25) (1984) 57 एसटीसी 322।

(26) 1991 एसटीसी 512।

(27) (1991) 83 एसटीसी 251 (एससी)

(28) (1990) 71 एसटीसी 71 (एससी)

(29) 80 एसटीसी 79 (एससी,)

(66) जब सूक्ष्मता से जांच की गई, तो निर्णय से पता चला कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केवल धारा के 'चार्जिंग भाग' से निपटा था, और उन परिस्थितियों का उल्लेख किया था जिनके तहत कर लगाया जाना था। परिस्थितियों को "परिणामों' के रूप में वर्णित किया गया था जो धारा की भाषा में प्रवाहित होते हैं...'..." ऊपर उल्लेखित है। छूट के संबंध में, राज्य द्वारा या उसकी ओर से कोई तर्क नहीं दिया गया। राज्य की ओर से उपस्थित वकील ने निम्नानुसार प्रस्तुत किया:—■

> "अगर दावा स्वीकार भी कर लिया जाए, तो भी .आकलन बेहतर स्थिति में नहीं होंगे। उन्होंने इसका पूरा समर्थन किया. उच्च न्यायालय के तर्क और आग्रह किया गया कि धारा की उप-धारा (1) के "अर्थ के भीतर" शब्दों को पूर्ण प्रभाव दिया जाना चाहिए, जिन्हें धारा 9 (आई) (बी) में जगह मिली जब तक कि उन्हें हटा नहीं दिया गया। 1988 का अधिनियम 1। यदि इन शब्दों पर उचित ध्यान दिया जाए, तो उन्होंने बताया कि करदाता विवादित खरीद कर से छूट के हकदार होंगे, केवल तभी जब उनकी बिक्री धारा के अर्थ के भीतर निर्यात बिक्री हो / केंद्रीय बिक्री, कर अधिनियम की धारा 5(1)' जिसे वे, स्वीकार करते हैं, नहीं थे। उन्होंने प्रस्तुत किया कि . यह तर्क कि, धारा 5(3) के अंतर्गत आने वाले मामलों में धारा 9(1) द्वारा लगाया गया कर लगाना, लेकिन केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 5(1) के अंतर्गत नहीं, संविधान के अनुच्छेद 286 का उल्लंघन होगा, गलत था और नजरअंदाज कर दिया गया महत्वपूर्ण परिस्थितियाँ कि धारा 9(1)(बी) में कच्चे माल की खरीद पर कर लगाया जाता है, न कि विनिर्मित वस्तुओं पर जो अंततः निर्यात की गईं। वैकल्पिक रूप से, वह धारा प्रस्तुत करते हैं। 9(1)(बी) को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। *गुडइयर मामले* में इस न्यायालय द्वारा और, इसलिए, करदाता इसकी भाषा से कोई निहित छूट नहीं मांग सकते हैं। यदि धारा 9 को छोड़ दिया जाता है, तो वह कहते हैं, धारा 6 (संशोधित) की भाषा, जो सभी खरीद और बिक्री पर शुल्क लगाती है राज्य में आकर्षित किया जाएगा और इसलिए खरीद का विवादित कराधान क्रम में होगा।

(67) रेफर करने के बाद *मो. सै) राजुद्दीन बनाम* उड़ीसा *राज्य* (30) /केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 5 के साथ-साथ धारा 9(1) (ए) (ii) और धारा 9(1) (बी) के प्रावधान खोजें और धारा 9 में संशोधनों को ध्यान में रखते हुए। उस मामले में न्यायालय आयोजित : -

> "उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय का निष्कर्ष सही था

> निर्धारिती धारा 9 के तहत छूट का हकदार नहीं था क्योंकि उसके द्वारा की गई बिक्री 'केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 5(1) के अर्थ के तहत भारत के क्षेत्र के बाहर निर्यात के दौरान बिक्री नहीं थी।'

(63) सुप्रीम कोर्ट ने मामले की परिस्थितियों में माना कि हालांकि, खंड की भाषा पर आने वाले दो अन्य परिणामों के बारे में कुछ भी असंवैधानिक नहीं है, एक व्यक्त और दूसरा निहित, एक राजस्व के पक्ष में और दूसरा राजस्व के पक्ष में करदाता. अधिनियम की धारा 9 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए, यह देखा गया:

> "जैसा कि ऊपर बताया गया है, धारा 9(1) शुल्क लगाने और छूट देने वाली दोनों धारा है।"

(69) *मुरली मनोहर के मामले (सुप्रा)* में सुप्रीम कोर्ट ने *गुडइयर के मामले* (सुप्रा) में निर्धारित कानून पर विचार किया, व्याख्या की और उसका उल्लेख किया । हालाँकि, *होटल बालाजी के मामले (सुप्रा)* में , *गुड ईयर केस (सुप्रा)* में सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले को खत्म कर दिया गया था।

(70) *होटल बालाजी के मामले (सुप्रा)* में , सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात बिक्री कर अधिनियम, यूपी बिक्री कर अधिनियम और आंध्र प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम की संवैधानिकता की जांच की। निर्धारिती ने *गुड ईयर केस (सुप्रा)* में न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया था, जबकि राजस्व की ओर से उपस्थित वकील न उक्त निर्णय की सत्यता को चुनौती दी थी और इस पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया था। संदर्भ में, अन्य राज्यों से संबंधित मामले, अन्य बातों *के अलावा, अच्छे वर्ष के* मामले (सुप्रा) के अनुपात से संबंधित प्रश्न पर भी विचार किया गया। हालाँकि, न्यायालय ने संकेत दिया कि वे अपना ध्यान केवल तीन राज्यों गुजरात, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के अधिनियमों तक ही सीमित रखेंगे। इस संदर्भ में *गुड ईयर केस (सुप्रा)* में निर्धारित कानून को अच्छा कानून नहीं माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात बिक्री कर अधिनियम की धारा 15-बी के प्रावधानों पर इस प्रकार विचार किया। गुजरात बिक्री कर अधिनियम (1990 का अधिनियम 6) द्वारा प्रतिस्थापित, जिसे 1990 के अधिनियम संख्या 7 द्वारा संशोधित किया गया और 6

मई, 1990 को बॉम्बे बिक्री कर अधिनियम की जगह लागू हुआ, जो उस समय तक उस राज्य में लागू था। अधिनियम की धारा 15 एक डीलर द्वारा **ऐसे व्यक्ति से की गई खरीद पर खरीद कर लगाती है जो पंजीकृत** डीलर नहीं है । धारा 15-ए 1983 के संशोधन अधिनियम संख्या 7 द्वारा प्रस्तुत की गई थी जिसमें कच्चे माल की खरीद के संबंध में **रियायती दर पर कर लगाने का प्रावधान था।**

किसी मान्यता प्राप्त डीलर द्वारा जो आवश्यक रूप से विनिर्माण करते हुए पाया गया, बशर्ते उनके द्वारा खरीदा गया सामान और कच्चा माल अनुसूची II या III में आता हो। धारा 15-बी को 1986 के संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था, जिसमें विनिर्माण डीलरों द्वारा खरीदे गए कच्चे माल पर अतिरिक्त खरीद कर लगाने का प्रावधान था, यदि वह उक्त कच्चे माल का उपयोग अन्य वस्तुओं के निर्माण के लिए करता था, जिसे वह अपने स्थान पर भेजता था। व्यवसाय का या उसके एजेंट के व्यवसाय का स्थान जो राज्य के बाहर लेकिन भारत के भीतर स्थित है। 1987 के अधिनियम में संशोधन करके, धारा को बिना किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन के प्रतिस्थापित कर दिया गया। *गुड ईयर केस (सुप्रा)* में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद , गुजरात उच्च न्यायालय में धारा 15-बी की वैधता को इस आधार पर चुनौती देते हुए कई रिट याचिकाएं दायर की गईं कि वास्तव में और प्रभाव में यह एक कंसाइनमेंट टैक्स लगाता है जो कि था राज्य विधानमंडल की क्षमता से बाहर। जबकि रिट याचिकाएँ लंबित थीं, अधिनियम की धारा 15-बी को 20 अप्रैल, 1990 को जारी किए गए 1999 के अध्यादेश संख्या 3 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। इसके बाद, 1990 के गुजरात बिक्री कर संशोधन अधिनियम 6 को अध्यादेश के स्थान पर अधिनियमित किया गया था। . प्रतिस्थापित धारा 15-बी को उस तारीख से पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया जब धारा 15-बी पहली बार लागू हुई थी। पेश किए गए तर्कों में यह शामिल था कि नए प्रावधान द्वारा लगाई गई लेवी उत्पाद शुल्क की प्रकृति में थी जो राज्य विधानमंडल की क्षमता से परे थी।

(71) हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने संयोगवश हरियाणा अधिनियम की धारा 9 और बॉम्बे बिक्री कर अधिनियम की धारा 13-एए के प्रावधानों का उल्लेख किया और खुद से सवाल पूछा कि उपरोक्त दोनों कानूनों में से किसी में कराधान की स्थिति क्या थी। इस मुद्दे को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया था, "सवाल यह है कि क्या कर की वसूली जीबीओडी की खरीद पर है या निर्मित वस्तुओं की खेप पर है।" सुप्रीम कोर्ट ने माना कि उक्त प्रावधान द्वारा बनाई गई लेवी राज्य के भीतर खरीदे गए कच्चे माल की खरीद पर एक लेवी है जिसका उपयोग राज्य के भीतर अन्य वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। यदि निर्मित माल राज्य के भीतर बेचा जाता है, तो कच्चे माल पर कोई बिक्री कर नहीं लिया जाता है, जाहिर है क्योंकि ऐसे माल की बिक्री पर कर लगाने से राज्य को बड़ा राजस्व मिलता है। जहां निर्मित माल राज्य के भीतर बेचा जाता है, लेकिन अभी तक उसका निपटान नहीं किया जाता है या जहां निर्मित माल राज्य के बाहर भेजा जाता है, वहां कच्चे माल के खरीद मूल्य पर कर

का भुगतान किया जाना है, इस कारण से कि निर्मित माल का अन्यथा निपटान किया जाता है। राज्य के बाहर बिक्री की तुलना में, राज्य को कोई राजस्व नहीं मिलता है क्योंकि राज्य के भीतर निर्मित वस्तुओं की कोई बिक्री नहीं होती है। ऐसी स्थिति में, यह माना गया कि राज्य ने लेवी और संग्रहण को बरकरार रखा है और माफ करने का कोई कारण नहीं था

इन दो स्थितियों में खरीद कर. यह देखा गया कि अंतर-राज्य बिक्री के मामले में, हरियाणा राज्य को संविधान के अनुच्छेद 269 के तहत कर राजस्व मिलता है। हालाँकि, यह देखा गया:

> "जहां, निश्चित रूप से, बिक्री केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम (एक्सपर्ट सेल्स) की धारा 5(1) के तहत एक निर्यात बिक्र है, राज्य को कोई राजस्व नहीं मिल सकता है लेकिन इससे बड़े राष्ट्रीय हित की पूर्ति होती है। इन्हीं कारणों से इन दोनों स्थितियों में कच्चे माल की खरीद पर टैक्स माफ किया जाता है।'

(72) *यूसुफ शबीर* बनाम *केरल राज्य* (31) में केरल उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को मंजूरी दे दी। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि केरल उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण हरियाणा अधिनियम की धारा 9 की योजना के बारे में उनकी समझ के अनुरूप है, जिससे कोई अस्पष्टता न रहे। न्यायालय ने कहा:-

> " दोहराने के लिए, हरियाणा अधिनियम की धारा 9 की योजना कच्चे माल की खरीद पर कर लगाने के लिए है और जहां उनसे निर्मित माल का निपटान किया जाता है (या भेजा जाता है, जैसा भी मामला हो) इसे छोड़ना नहीं है। इस तरीके से राज्य को कोई राजस्व नहीं मिल रहा है और न ही राष्ट्र और इसकी अर्थव्यवस्था के हितों की सेवा हो रही है, जैसा कि यहां पहले बताया गया है। खरीदी गई वस्तुओं को अन्य वस्तुओं के निर्माण में उनकी खपत से समाप्त कर दिया जाता है और फिर भी निर्मित वस्तुओं को इस तरह से निपटाया जाता है कि राज्य किसी भी राजस्व से वंचित हो जाए, ऐसे मामलों में, कोई कारण नहीं है कि राज्य को इसे छोड़ना चाहिए कच्चे माल की खरीद पर इसका कर राजस्व।

(73) *बालाजी के मामले* (सुप्रा) में न तो हरियाणा राज्य एक पक्ष था और

न ही इसका उचित प्रतिनिधित्व किया गया प्रतीत होता है। मुद्दे का मुद्दा यह भी नहीं था कि क्या अधिनियम की धारा 9 छूट प्रदान करती है और पहले के निर्णय के आधार पर निर्यात बिक्री के पक्ष में छूट पर विचार किया गया था। जहां तक *मुरली मनोहर* (सुप्रा) के मामले का संबंध है, यह कहा गया था:

(31) (1973) 32 एसटीसी 359।

> " यह हरियाणा बिक्री कर अधिनियम के तहत उत्पन्न हुआ और अधिनियम की धारा 9(1)(बी) में संदर्भित निर्यात बिक्री का अर्थ बताता है। इस फैसले में हमारे सामने मौजूद मुद्दे के बारे में कोई चर्चा नहीं है।"

हालाँकि, फैसले से अलग होने से पहले, सुप्रीम कोर्ट ने मामले का एक और पहलू स्पष्ट किया और कहा: -

> "यह हमारे ध्यान में लाया गया कि हरियाणा और बॉम्बे दोनों प्रावधानों को पूर्वव्यापी प्रभाव से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। हमने इस भाग में उन प्रावधानों का उल्लेख नहीं किया है, इस कारण से कि हम केवल अच्छे वर्ष में तर्क से चिंतित हैं।

(74) इस प्रकार यह स्पष्ट होगा कि धारा 9 के तहत छूट हमारे समक्ष राज्य की ओर से उठाए गए विवादों का निर्धारण किए बिना मान ली गई थी और राज्य के दृष्टिकोण को ठीक से पेश नहीं किया गया था क्योंकि उस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय मुख्य रूप से चिंतित था। तीन राज्यों अर्थात् गुजरात, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बिक्री कर के साथ।

(75) *जगतजीत शुगर मिल्स* बनाम *पंजाब राज्य और अन्य (32)* मामले में , सुप्रीम कोर्ट ने धारा 4-बी के उद्देश्य और उद्देश्य1948 and found it to be पर विचार किया।
पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम की धारा 9
बिक्री कर अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप। of the Haryana General plea of the petitionerr manufacturing Sugar cane3 growersS and1 co-
उस मामले में, वह चीनी कैनी की खरीद के उद्देश्य से था
ऑपरेटिव सोसायटी और चूंकि गन्ना एक कृषि उपज है, इसलिए इसे अनुसूची 'बी' के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 6 के अर्थ के तहत बिक्री कर के भुगतान से छूट दी गई थी और क्योंकि उक्त गन्ना
गन्ना उत्पादकों द्वारा स्वयं याचिकाकर्ता-मिल को बेचा गया था, गन्ने की बिक्री या खरीद पर कोई बिक्री कर या खरीद कर नहीं लगाया जा सकता था। *होटल बालाजी के मामले (सुप्रा)* सहित कई अधिकारियों पर विचार करने के बाद , सुप्रीम कोर्ट ने अंततः कॉस्ट के साथ रिट याचिका को खारिज कर दिया। हालाँकि, धारा 4-बी के दायरे से निपटते समय, सुप्रीम कोर्ट ने कहा: -

" यदि विनिर्मित वस्तुओं को राज्य से इस प्रकार बाहर ले जाया जाता है कि राज्य को कोई कर प्राप्त नहीं होता (न ही)

(32) 1995 (96) एसटीसी 344 (एससी)।

उपरोक्त राष्ट्रीय हित की पूर्ति होती है), कच्चे माल की खरीद पर कर लगाया जाता है। इसके विपरीत, यदि निर्मित माल राज्य के भीतर बेचा जाता है या अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान बेचा जाता है या निर्यात के दौरान बेचा जाता है, तो कच्चे माल को खरीद कर से छूट दी जाती है। हालाँकि, यदि विनिर्मित वस्तुएँ अनुसूची बी में शामिल हैं - बिक्री बिंदु पर कर योग्य नहीं हैं - खंड (i) उनके निपटान के तरीके से संबंधित नहीं है। राजस्व के दृष्टिकोण से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऐसा सामान राज्य के भीतर बेचा जाता है या अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान बेचा जाता है या निर्यात के दौरान बेचा जाता है; किसी भी स्थिति में, राज्य को कोई राजस्व प्राप्त नहीं होता है।"

(76) न्यायालय ने यह भी पाया कि धारा 4-बी को कुछ निर्दिष्ट स्थितियों में कुछ वस्तुओं की खरीद पर, जैसा भी मामला हो, खरीद कर की पुष्टि या छूट देने के लिए डिज़ाइन किया गया था। धारा का उद्देश्य यह माना गया था कि कच्चे माल की खरीद पर कर नहीं लगाया जाता था, जहां निर्मित वस्तुओं की बिक्री से राज्य को कर मिलता है या राष्ट्रीय हित की पूर्ति होती है। न्यायालय ने माना कि चूंकि धारा 4-ब अनुसूची 'बी7वस्तुओं पर लागू नहीं होती, इसलिए उक्त प्रावधान याचिकाकर्ताओं के लिए प्रासंगिक नहीं था क्योंकि गन्ने पर खरीद कर धारा 4(1) द्वारा लगाया गया था।

(77) *होटल बालाजी मामले* (सुप्रा) और *मुरली मनोहर मामले (सुप्रा)* में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मद्देनजर याचिकाओं को स्वीकार किया जाना आवश्यक है और याचिकाकर्ताओं को हरियाणा अधिनियम की धारा 9 के तहत छूट का हकदार माना जाता है। और पंजाब अधिनियम की धारा 4।

(78) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील के इस तर्क की सराहना करने के लिए संविधान के विभिन्न प्रावधानों और इस विषय पर सर्वोच्च न्यायालय की घोषणाओं का संदर्भ होना आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 141 में प्रावधान है कि सर्वोच्च

न्यायालय द्वारा घोषित कानून1 भारत के क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। यह अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को किसी कानून की व्याख्या करने के अपन कार्यों के दौरान कानून घोषित करने का अधिकार देता है । कानून को विशेष परिवर्तनों के अनुरूप लाने के लिए ऐसी शक्ति पर विचार किया जाता है (AIR 1968 SC 683)। यह *अमृतसर नगर पालिका* बनाम *हजारा सिंह* (33) में आयोजित किया गया था, जिसमें प्रत्येक कथन शामिल था

(33) एआईआर 1975 एससी 1087।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले में संविधान के अनुच्छेद 141 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। कानून के अलावा अन्य मामलों पर बयानों में कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं होती है। इसी प्रकार *गुरुचरण सिंह* बनाम *पंजाब राज्य* (34) और *प्रकाश चंदर पैहाक* बनाम *उत्तर प्रदेश राज्य (35)* में , यह माना गया कि तथ्यों के आधार पर, कोई भी दो मामले समान नहीं हो सकते हैं, निर्णय जो अनिवार्य रूप से प्रश्नों पर होते हैं अन्य मामलों के निर्णय के लिए तथ्यों पर मिसाल के तौर पर भरोसा नहीं किया जा सकता। *लक्ष्मी शंकर श्रीवास्तव* बनाम *राज्य (दिल्ली प्रशासन) एआईआर 1979 एससी 451* मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संबंधित प्रावधानों के किसी भी विश्लेषण या परीक्षण पर नहीं बल्कि रियायत पर चल रहे फैसले को कानून के अर्थ में घोषित करने वाला नहीं माना जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 141. यह देखने के लिए कि क्या सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 141 के अर्थ के भीतर कानून बनाया है, विचार के लिए उठे प्रश्नों के संदर्भ पर ध्यान देना आवश्यक है जिसमें निर्णय दिया गया था और एक का तर्क निर्णय को अन्य मामलों पर तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि स्थित और परिस्थितियों में समानता न हो। दूसरे आदेश को एक उदाहरण के रूप में नहीं माना जा सकता है, खासकर जब ऐसा पाया जाता है कि ऐसा आदेश विशेष रूप से जुड़ा हुआ नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामला चल रहा है। हालाँकि ओबिटर डिक तुम अभी तक कोई मिसाल नहीं है। देश में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी सम्मान और महत्वपूर्ण महत्व के योग्य है।

(79) सेंट्रल के जिन्स *असिस्टेंट ई कलेक्टर ई* बनाम *डनलप इंडिया लिमिटेड और अन्य (36) ने देश में न्याय देने* की प्रणाली का उल्लेख किया और आशा व्यक्त की कि देश में अदालतों की पदानुक्रमित प्रणाली *में* उच्च न्यायालय सहित प्रत्येक

निचले स्तर के लिए यह आवश्यक था कि वह उच्च स्तर के निर्णय को निष्ठापूर्वक स्वीकार करे। *कैसेल एंड कंपनी* बनाम *ब्रूम* (37) का जिक्र करते हुए , उनके आधिपत्य ने कहा: -

> "हम जोड़ना चाहते हैं और जैसा कि *कैसेल एंड कंपनी लिमिटेड* बनाम *ब्रूम में कहा गया था,* हमें उम्मीद है कि हमारे लिए ऐसा दोबारा कहना कभी जरूरी नहीं होगा कि "हमारे देश में मौजूद अदालतों की पदानुक्रमित प्रणाली में, यह आवश्यक है प्रत्येक निचले स्तर", जिसमें उच्च न्यायालय भी शामिल है, "निर्णयों को निष्ठापूर्वक स्वीकार करना

(34) 1972 एफएसी 549.

(35) एआईआर 1960 एससी 195।

(36) 1935 1 एससीसी 380।

(37)1 1972एए.सी.1 1027((1972((1)4एलईइंजी.ईरिपोर्ट8 801)

उच्च स्तरों का "। अदालतों की पदानुक्रमित प्रणाली में यह अपरिहार्य है कि सर्वोच्च अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले होते हैं जो न्यायपालिका के सभी सदस्यों की सर्वसम्मत मंजूरी को आकर्षित नहीं करते हैं, लेकिन न्यायिक प्रणाली केवल तभी काम करती है जब किसी को अंतिम शब्द और वह अंतिम बोलने की अनुमति दी जाती है। एक बार बोला गया शब्द निष्ठापूर्वक स्वीकार किया जाता है।" निचली अदालत के बेहतर ज्ञान को ऊपर की अदालत के उच्चतर ज्ञान के अनुरूप होना चाहिए। यह पदानुक्रमित न्यायिक प्रणाली की ताकत है। ***कैसेल एंड कंपनी लिमिटेड*** बनाम ***ब्रूम*** में , अपील न्यायालय की टिप्पणी पर टिप्पणी करते हुए कि ***रूकीज़*** बनाम ***बर्नार्ड क*** ***प्रति इन्क्यूरियम*** प्रस्तुत किया गया था , लॉर्ड डिप्लॉक ने कहा:

"अपील की अदालत ने खुद को ***रूकीज़*** बनाम ***बरनार्ड में इस सदन के निर्णय की अवहेलना करने में सक्षम पाया***, इस पर लेबल प्रति इंक्यूरियम लागू करके। यह लेबल केवल अपीलीय अदालत के अपने पिछले निर्णयों में से किसी एक का पालन करने से इनकार करने के अधिकार के लिए प्रासंगिक है, न कि उच्च अपीलीय अदालत के फैसले की अवहेलना करने के अधिकार या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अवहेलना करने के अधिकार के लिए। अपील की अदालत का एक निर्णय।

"यह जोड़ने की आवश्यकता नहीं है कि भारत में संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा और अनुच्छेद 144 के तहत भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण, नागरिक और न्यायिक कार्य करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की सहायता में।"

(80) ***एस*** इन ***शमा राव*** बनाम डब्ल्यूओ ***यूनियन*** री ***टेरिटरी***।, (38) में, यह कहा गया था, "यह कहना सामान्य है कि निर्णय अपने निष्कर्ष के मामले में बाध्यकारी है, लेकिन इसके अनुपात और उसमें निर्धारित सिद्धांत के संबंध में है । "। ***शेनॉय एंड कंपनी*** बनाम ***वाणिज्यिक कर अधिकारी*** (39) में । उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसी को भी यह आग्रह करने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि शीर्ष न्यायालय का निर्णय उस व्यक्ति के मामले में लागू नहीं होगा जो उस न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं था। उनके आधिपत्य ने माना कि ऐसे मामले में जहां कई याचिकाओं का निपटारा एक सामान्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है , पीड़ित पक्ष एक अपील दायर कर सकता है और अन्य पक्ष-

(38) एआईआर 1967 एससी 1180।

(39) 1985 (ii) एससीसी 512।

उन्होंने यह कहते नहीं सुना कि यह निर्णय अदालत ने उनकी पीठ पीछे लिया था, या इस तथ्य से अनभिज्ञ थे कि सामान्य फैसले के खिलाफ राज्य द्वारा अपील दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक आर्थिक प्रक्रिया के रूप में पाया और घोषित किया कि "यह तर्क देना कि यह निष्कर्ष केवल इस न्यायालय के समक्ष पक्ष पर लागू होता है, निर्णय की प्रभावकारिता और अखंडता को नष्ट करना और अनुच्छेद 141 के आदेश को भ्रामक बनाना है।" उनके आधिपत्य ने आगे कहा कि ऋण की घोषणा हर किसी के लिए बाध्यकारी है और यह मानना व्यर्थ है कि *परमादेश* उन पक्षों के पक्ष में रहेगा जिनके खिलाफ अपील दायर की गई थी।

ऐसी स्थिति का जिक्र करते हुए न्यायालय ने कहा:-

> "थोड़े अलग कोण से प्रस्तुत प्रस्तुतियों को देखकर तर्क की भ्रांति को बेहतर ढंग से चित्रित किया जा सकता है। तर्क के लिए मान लें कि इस न्यायालय के फैसले के बावजूद अपीलकर्ताओं के पक्ष में *परमादेश कायम रहा।* वे *परमादेश को कैसे लागू करते हैं?* सामान्य प्रक्रिया यह है कि जब जिन पक्षों के खिलाफ *परमादेश* जारी किया गया है, वे इसका अनादर करते हैं तो अवमानना के मामले में अदालत का रुख करें। मान लीजिए कि अवमानना याचिकाएं दायर की जाती हैं और राज्य को नोटिस जारी किए जाते हैं। अदालत को राज्य का जवाब होगा "क्या मुझे जारी किए गए *परमादेश का* अनादर करने के लिए दंडित किया जा सकता है , कौन सा कानून मेरे और आपके लिए समान रूप से बाध्यकारी है?" इन परिस्थितियों में कौन सी अदालत किसी पक्ष को अवमानना के लिए दंडित कर सकती है? उत्तर केवल नकारात्मक हो सकता है क्योंकि उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया *परमादेश तब अप्रभावी और* अप्रवर्तनीय हो जाता है जब जिस आधार पर इसे जारी किया गया था, वह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1979 के अधिनियम की वैधता को समाप्त कर दिया जाता है।

(81) संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित डिक्री और आदेश भारत के क्षेत्र में इस तरह से लागू किए जा सकते हैं जैसे कि संसद द्वारा या उसके द्वारा बनाए गए कानून के तहत निर्धारित किया जा सकता है। *यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन* में अनुच्छेद 142 के दायरे पर सुप्रीम कोर्ट ने

विचार किया था । बनाम भारत *संघ* (40), जिसमें यह आयोजित किया गया था: —

> "इस न्यायालय की शक्तियों के दायरे को छूने वाले तर्कों में कुछ गलतफहमियों को दूर करना आवश्यक है

(40) ए.एल.आर. 1992 एससी 248.

कला के तहत. संविधान के <142(1). ये मुद्दे गंभीर सार्वजनिक महत्व के मामले हैं। यह प्रस्ताव कि किसी भी सामान्य कानून में एक प्रावधान, सार्वजनिक नीति के महत्व की परवाह किए बिना, जिस पर वह आधारित है, अनुच्छेद 142(1) के तहत शीर्ष न्यायालय की शक्तियों को सीमित करने के लिए काम करता है, निराधार और गलत है। गैंग का मामला और अंतुले का मामला, दोनों में मुद्दा संवैधानिक प्रावधानों और संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन का था। वैधानिक प्रावधानों के साथ असंगति के प्रभाव के बारे में टिप्पणियाँ उन मामलों में वास्तव में आवश्यक थीं क्योंकि अंतिम विश्लेषण में निर्णय संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन पर आधारित थे। हम श्री नरीमन से सहमत हैं कि कला के तहत न्यायालय की शक्ति। 142 जहां तक आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का सवाल है, एसएस द्वारा समाप्त नहीं किया गया है। 320 या 482 Cr.PC या ये सभी एक साथ। कला के तहत शक्ति. 142 एक भिन्न गुणवत्ता का पूर्णतः भिन्न स्तर है। सामान्य कानूनों में निहित निषेध या सीमाएँ या प्रावधान *वास्तव में* कला के तहत संवैधानिक शक्तियों पर निषेध या सीमाओं के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं। 142. क़ानून में इस तरह के निषेध या सीमाएं किसी विशेष कानून की योजना को मूर्त रूप दे सकती हैं और प्रतिबिंबित कर सकती हैं। प्राधिकरण या न्यायालय की प्रकृति और स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जिस पर कुछ उचित तरीके से सीमित शक्तियां प्रदान करने पर विचार किया जाता है। सीमाएं आवश्यक रूप से सार्वजनिक नीति के किसी मौलिक विचार को प्रतिबिंबित या उस पर आधारित नहीं हो सकती हैं। विद्वान अटॉर्नी जनरल श्री सोराबजी ने गर्ग के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि कला के तहत शक्तियों पर प्रतिबंध है। 142 " मौलिक कानून के स्पष्ट वैधानिक प्रावधानों के साथ असंगतता*' से उत्पन्न होने का वास्तव में किसी भी मूल वैधानिक कानून में निहित कुछ स्पष्ट निषेध के रूप में अर्थ और समझा जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि 'प्रावधान' के स्थान पर स्पष्ट 'निषेध' पढ़ा जाए तो शायद यह उचित

विचार व्यक्त करेगा। लेकिन हमारा मानना है कि इस तरह का निषेध सार्वजनिक नीति के कुछ अंतर्निहित बुनियादी और सामान्य मुद्दों पर आधारित होना चाहिए, न कि केवल किसी विशेष वैधानिक योजना या पैटर्न के लिए आकस्मिक। यह कहना फिर से पूरी तरह से गलत होगा कि कला के तहत शक्तियाँ। 142 ऐसे स्पष्ट वैधानिक निषेध के अधीन हैं । इससे यह विचार व्यक्त होगा कि वैधानिक समर्थक दृष्टिकोण संवैधानिक प्रावधान पर हावी हो जाते हैं। शायद विचार व्यक्त करने का उचित तरीक व्यायाम ही है

कला के तहत शक्तियाँ। 142 और किसी कारण या मामले के "पूर्ण न्याय" की जरूरतों का आकलन करने में, शीर्ष न्यायालय सार्वजनिक नीति के कुछ मौलिक सिद्धांतों के आधार पर किसी भी मूल वैधानिक प्रावधान में स्पष्ट निषेधों पर ध्यान देगा और अपनी शक्ति के अभ्यास को विनियमित करेगा और तदनुसार विवेक. यह प्रस्ताव कला के तहत न्यायालय की शक्ति से संबंधित नहीं है। 142, लेकिन केवल इस बात पर कि किसी कारण या मामले का 'पूर्ण न्याय' क्या है या नहीं और शक्ति के प्रयोग के औचित्य के अंतिम विश्लेषण में। क्षेत्राधिकार की कम या अशक्तता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

विद्वान अटॉर्नी जनरल ने कहा कि धारा 320 आपराधिक प्रक्रिया संहिता "उन परिस्थितियों और शर्तों से परिपूर्ण है जिनके तहत संरचना प्रभावित हो सकती है"

और 'अदालत उन वर्गों या अपराधों का निर्धारण करने के लिए विधायिका द्वार निर्धारित परीक्षण से आगे नहीं जा सकती है जो समझौता योग्य हैं और उनमें से किसी एक को स्थानापन्न करें?' विद्वान अटॉर्नी जनरल ने *विश्वबाहन* बनाम *गोपेन चंद्रा* (1967 1 एससीआर 447 पी. 451, एआईआर 1967 एससी 895 पृष्ठ 897) में निम्नलिखित परिच्छेद का भी उल्लेख किया है, यदि किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप लगाया गया है, तो जब तक कि समझौते के लिए कोई प्रावधान न हो इसमें, कानून को अपना काम करना चाहिए और आरोप की जांच करनी चाहिए जिसके परिणामस्वरूप या तो दोषी ठहराया जाएगा या बरी कर दिया जाएगा।"

(82) उन्होंने कहा कि 'अगर किस आपराधिक मामले को गैर-समझौता योग्य घोषित किया जाता है, तो इसे समझौता करना सार्वजनिक नीति के खिलाफ है। और उस अंत तक कोई भी समझौता कानून में पूरी तरह से शून्य है"

और प्रस्तुत किया कि न्यायालय "उस चीज़ को कानूनी नहीं बना सकता जिसकी कानून निंदा करता है"। विद्वान अटॉर्नी जनरल ने इस बात पर जोर दिया कि आपराधिक मामला एक स्वतंत्र मामला था और बड़ी सार्वजनिक

चिंता का विषय था और यह किसी समझौते या समझौते का विषय नहीं हो सकता था। यह कहने का कुछ औचित्य है कि गंभीर अपराधों के कुछ वर्ग, जिनमें बड़े सामाजिक हित और सामाजिक सुरक्षा शामिल हैं, की कंपाउंडिंग के खिलाफ वैधानिक निषेध सार्वजनिक नीति के व्यापक और मौलिक विचार पर आधारित है। लेकिन जरूरी नहीं कि सभी वैधानिक निषेधों में यह गुण शामिल हो। अनुच्छेद के तहत महत्वपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने की शीर्ष अदालत की शक्ति पर हमला। 142(1) की कल्पना गलत है। लेकिन इसके अभ्यास का औचित्य एक और मामला है।

इस फैसले के मद्देनजर एसएलपी में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया। (सी) 1993 की संख्या 4208-09 को उचित समय पर यह निर्धारित करने के लिए बनाया जाएगा कि क्या कोई निर्देश दिया गया था या

कला के संदर्भ में उनके आधिपत्य द्वारा पारित आदेश। 142 का संविधान।

(83) *कौशल्या देव बोयरा* बनाम भूमि *अधिग्रहण अधिकारी (41)* में , सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कैसेल एंड कंपनी (सुप्रा) के मामले का उल्लेख किया और कहा कि, "अपीलीय अदालत का निर्देश निश्चित रूप से उसके अधीनस्थ अदालतों पर बाध्यकारी है। इसके अलावा, कला के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए। संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार भारत की सभी अदालतें इस अदालत के निर्णयों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। न्यायिक अनुशासन के लिए आवश्यक है और कानून की मर्यादा यह सुनिश्चित करती है कि अपीलीय निर्देशों को बाध्यकारी माना जाए और उनका पालन किया जाए। " *बिक्रमजीत सिंह* बनाम *मध्य प्रदेश राज्य* (एआईआर 1992 एससी 474) में, यह यथावत रखा गया था। "ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान न्यायाधीश आक्षेपित आदेश पारित करते समय इस बात की सराहना करने में विफल रहे कि कोई भी पीठ उसी अदालत की समन्वय पीठ के कामकाज पर टिप्पणी नहीं कर सकती है, यहां तक कि उसके फैसले पर अपीलीय अदालत के रूप में निर्णय लेना तो दूर की बात है।" ए. *आर. अंतुले* बनाम *आर.एस. नेल* (42) में , यह आयोजित किया गया था: -

> "हालाँकि, वैधता का प्रश्न महत्वपूर्ण है। इसमें क्षेत्राधिकार की कमी को केवल एक उच्च न्यायालय द्वारा स्थापित किया जा सकता है और व्यवहार में, किसी भी निर्णय को किसी भी निचली अदालत द्वारा संपार्श्विक रूप से महाभियोग नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन सुपीरियर कोर्ट हमेशा याचिका या एर *डेबिटो* जस्टिसैक के माध्यम से अपने ध्यान में लाई गई अपनी त्रुटि को सुधार सकता है ।

(84) संविधान के अनुच्छेद 144 में यह प्रावधान है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण, नागरिक और न्यायिक, सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे और अनुच्छेद 145 सनरेम न्यायालय को उसमें उल्लिखित उद्देश्यों के लिए आम तौर पर अभ्यास और प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने के लिए अधिकृत करता है।

(85) पक्षों के विद्वान वकील ने अभिव्यक्ति 'प्रति इंक्यूरियम' के संबंध में कुछ निर्णयों का उल्लेख किया है, जिसका अर्थ है किसी क़ानून या क़ानून के बल वाले नियम के संदर्भ में अज्ञानता में दिया गया निर्णय। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को 'नेर इंक्यूरियम' कहे जाने के संबंध में इस मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए इस तर्क पर निर्णय देना आवश्यक नहीं हो सकता है।

(41) 1984 द्वितीय एससीसी 324।

(42) एआईआर 1988 एससी 1531।

(86) **जैसा कि ऊपर देखा गया है, विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करने के बाद, यह। यह माना जाता है कि:**

(1) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है;

(2) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून का अर्थ ऐसे कानून को सामाजिक परिवर्तनों के अनुरूप लाने के लिए कानून की व्याख्या करना है;

(3) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून न्यायालय के समक्ष विवादग्रस्त मामले के संबंध में होना चाहिए, न कि केवल एक आज्ञाकारी आदेश;

(4) भले ही सर्वोच्च न्यायालय के किसी आज्ञापालक को उचित सम्मान और पर्याप्त महत्व देने की आवश्यकता हो, तथ्यों पर रियायत के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में कोई बाध्यकारी बल नहीं होता है ;

(5) उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून, दिया गया निर्णय और पारित आदेश उच्च न्यायालय सहित देश की सभी अदालतों पर बाध्यकारी प्रकृति के हैं: और

(6) समन्वय पीठों के फैसले पर किसी अन्य पीठ द्वारा अपीलीय अदालत के रूप में टिप्पणी या निर्णय नहीं किया जाना चाहिए,

(87) *होटल बालाजी के मामले* (सुप्रा) और *मुरली मनोहर के मामले (सुप्रा)* में सुप्रीम कोर्ट के उपरोक्त निर्णयों में उल्लेख किया गया था , सुप्रीम कोर्ट ने अन्य राज्यों के कानून की व्याख्या करते समय अधिनियम के प्रावधानों का संदर्भ दिया था। अन्य राज्यों से संबंधित कानून के प्रावधानों की व्याख्या करते समय सुप्रीम कोर्ट के फैसले में की गई या नोट की गई ऐसी टिप्पणियों या विवादों को अंतिम रूप से तय नहीं माना जा सकता है क्योंकि माना जाता है कि हरियाणा अधिनियम को स्थगित करने के लिए नहीं कहा गया था । रियायतों पर कार्यवाही करने वाला निर्णय, चाहे वह अंतर्निहित हो या अंतर्निहित और स्वीकार्य रूप से विश्लेषण या प्रासंगिक प्रावधानों की जांच पर आधारित नहीं है, को संविधान के अनुच्छेद 141 के अर्थ के भीतर कानून घोषित करने वाला नहीं माना जा **सकता है ।** ओबिटर-डिक्टम को मिसाल के तौर पर नहीं माना जा सकता है, खासकर तब जब ऐसा ओबिटर-डिक्टम सुप्रीम कोर्ट के समक्ष किसी मुद्दे से विशेष रूप से जुड़ा हुआ नहीं पाया जाता है। हालाँकि, यह माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का ओबिटर-डिक्टम हालांकि कोई मिसाल नहीं है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट की **टिप्पणियाँ सम्मान के योग्य हैं।**

और काफी महत्व. यहां ऊपर जो नोट किया गया है और चर्चा की गई है, उसके आलोक में, उपरोक्त दो निर्णयों में निर्धारित कानून को इस न्यायालय के समक्ष विवाद में मामले के संबंध में निर्णय नहीं माना जा सकता है।

(88) *जगतजीत शुगर मिल्स के मामले (सुप्रा)* में माननीय सर्वोच्च न्यायालय केवल गन्ना उत्पादकों से गन्ना खरीदने वालों के दायित्व से चिंतित था, जिनके बारे में कह गया था कि वे संबंधित क़ानून के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। जैसा कि हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, अधिनियम की धारा 4-बी के दायरे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा *होटल बालाजी मामले* (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और टिप्पणियों के प्रति सबसे बड़ा सम्मान और सम्मान दिखाते हुए न तो बहस की गई, न ही विचार किया गया और न ही फैसला सुनाया गया। और *मुरली मनोहर के मामले* (सुप्रा) में, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि चूंकि न्यायालय ने हमारे समक्ष संबोधित तर्कों के संदर्भ में इस विषय पर कानून घोषित नहीं किया था, इसलिए सभी सम्मान और मूल्य रखते हुए याचिकाकर्ता द्वारा सेवा में दबाव नहीं डाला जा सकता है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उनके तर्कों को स्वीकार करने के लिए।

(89) निर्धारिती की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि यदि उनके ग्राहकों को धान पर खरीद कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है, तो मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा ब्याज की मांग करना उचित नहीं था, - याचिका में मांग नोटिस के माध्यम से /यह तर्क दिया गया है कि ब्याज की देनदारी के संबंध में कोई मांग नहीं की गई थी या अधिनियम की धारा 40 के तहत दिए गए नोटिस में इसका उल्लेख भी नहीं किया गया था, जब कर का भुगतान करने की देनदारी स्वयं अस्थिर स्थिति में थी और अनिश्चितता के किनारों पर लंगड़ा रही थी, ब्याज की कोई मांग नहीं थी उन याचिकाकर्ताओं से बनाया जा सकता है जिन्होंने *प्रामाणिक* कार्रवाई या चूक की छत्रछाया में सुरक्षा की मांग की है ।

(90) डिमांड नोटिस के अवलोकन से पता चलता है कि करदाताओं को अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (5) के अनुसार ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। यह उल्लेखनीय है कि ब्याज का भुगतान करने की गैर

देनदारी का दाव ब्याज लगाने वाले प्रावधानों को चुनौती दिए बिना किया गया है।

(01) अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (5) प्रदान करती है: -

(91) यदि (उप-धारा (2) में उल्लिखित कोई भी डीलर उप-धारा (3) के अनुसार अपेक्षित कर का भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह कर के अतिरिक्त देय राशि पर एक प्रतिशत प्रति साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। तारीख से महीना

उप-धारा (2) के तहत रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि के बाद की तारीख से शुरू होकर एक महीने की अवधि के लिए और उसके बाद की अवधि के दौरान प्रति माह डेढ़ प्रतिशत की दर से भुगतान में चूक जारी रहती है: -

बशर्ते कि जहां उप-धारा (3) के तहत अपेक्षित कर का भुगतान नहीं किया गया है, वह पांच सौ रुपये से अधिक नहीं है, उस पर देय ब्याज इस प्रकार भुगतान नहीं किए गए कर की राशि से अधिक नहीं होगा:

बशर्ते कि ब्याज की गणना के प्रयोजनों के लिए, पंद्रह दिन या उससे अधिक की अवधि को एक माह माना जाएगा और पचास रुपये या अधिक की राशि को एक सौ रुपये और पंद्रह दिनों से कम की अवधि के रूप में समझा जाएगा। पचास रुपये से कम की राशि को नजरअंदाज कर दिया जाएगा।

(92) को अधिनियम की धारा 25 की उपधारा 2 और उपधारा 3 के संदर्भ में कर का भुगतान करने के लिए कभी नहीं कहा गया था , उन्हें कथित रूप से देय राशि पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। उनके यहाँ से। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि न्यायिक घोषणाओं में विरोधाभास था और प्रतिवादी-राज्य स्वयं खरीद कर का भुगतान करने के लिए याचिकाकर्ताओं के दायित्व के बारे में स्पष्ट नहीं था, याचिकाकर्ताओं ने ईमानदारी से खरीद कर का भुगतान नहीं *किया*। आगे यह तर्क दिया गया है कि जब छूट के

वास्तविक विश्वास के तहत कर का भुगतान नहीं किया जाता है , तो निर्धारिती डीलर पर अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा 5 के संदर्भ में ब्याज का भुगतान करने के दायित्व का बोझ नहीं डाला जा सकता है।

(93) जैसा कि निर्णय के पहले भाग में उल्लेख किया गया है, खरीद-कर का भुगतान करने के लिए याचिकाकर्ताओं का दायित्व स्पष्ट रूप से विवाद में था और प्रतिवादी-अधिकारियों को भी स्पष्ट नहीं था। उपरोक्त नोटिस जारी होने की तारीख से बहुत पहले मूल्यांकन वर्षों के संबंध में स्वत: कार्रवाई करने का प्रस्ताव करने वाले अधिनियम की धारा 40 के *तहत* नोटिस जारी करना संकेतात्मक है, तथ्य का संकेत है और याचिकाकर्ताओं के अब तक के मामले को मजबूत करता है। जहां तक ब्याज की मांग का सवाल है. अधिनियम की धारा 40 के प्रावधानों का सहारा स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि याचिकाकर्ता को पहले उनकी कर देयता के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया था और पुनरीक्षण प्राधिकारी ने स्वयं ही मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा कथित रूप से निपटाए गए मामले के रिकॉर्ड को मंगाने का निर्णय लिया। कार्यवाही की वैधता या औचित्य के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने के प्रयोजनों के लिए

कर का भुगतान करने के लिए याचिकाकर्ताओं की देनदारी का निर्धारण करने वाले आदेश पारित करने से पहले उसमें दिए गए आदेश। यह उल्लेख करना उचित होगा कि पुनरीक्षण प्राधिकारी ने कर की मूल राशि के भुगतान में चूक के मामले में ब्याज का भुगतान करने के अपने दायित्व के संबंध में डीलर को संकेत भी नहीं दिय था। नियम 34 के तहत फॉर्म एसटी 28 पर मूल्यांकन के नोटिस में, मूल्यांकन प्राधिकारी ने अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा 5 के संदर्भ में उस अवधि और ब्याज की दर का उल्लेख नहीं किया है जिस पर देनदारी निर्धारित की गई थी। जहां तक मूल्यांकन आदेश ब्याज के भुगतान का निर्देश देता है वह अस्पष्ट और संदिग्ध है जो प्रथम दृष्टया अधिनियम की धारा 25 की उपधारा 5 की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। मामले की परिस्थितियाँ यह नहीं दर्शाती हैं या सुझाव भी नहीं देती हैं कि याचिकाकर्ता-डीलर ने धारा 25 के तहत निर्धारित समय के भीतर कर जमा करने में *दुर्भाविनापूर्ण कार्य किया था और इस प्रकार* उपरोक्त की उप-धारा 5 के तहत ब्याज का भुगतान करने के लिए कोई देनदारी उत्पन्न हुई थी। अनुभाग।

(94) यह सच है कि बिक्री कर किसी राज्य के लिए राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है और अधिनियम के तहत अधिकारियों को यह तय करना ह कि इस तरह के राजस्व की वसूली कैसे और किस तरीके से की जाएगी। कर के भुगतान में चूक के मामले में ब्याज के भुगतान का प्रावधान निर्धारिती को राज्य द्वारा निर्धारित समय के भीतर देय कर का भुगतान करने के लिए बाध्य करने का एक साधन है। हालाँकि, यह भी उतना ही सच है कि किसी नागरिक को बिक्री कर के कथित गैर-भुगतान के लिए ब्याज के रूप में जुर्माना देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, जब कर का भुगतान करने का दायित्व स्वयं विवाद में था *और* अधिकारी स्पष्ट नहीं थे निर्धारिती के दायित्व के बारे में. न तो दोषी करदाता को कानून की तकनीकीताओं के तहत कोई लाभ दिया जा सकता है और न ही राज्य को कर के भुगतान में चूक के मामले में ब्याज का भुगतान करने के दायित्व के साथ वास्तविक निर्धारिती पर *बोझ डालने की अनुमति दी जा सकती है;* जिसका दायित्व स्वयं गुड़िया ड्रम में है।

(95) *विटनी बनाम अंतर्देशीय राजस्व* आयुक्त (43) में लॉर्ड डुनेडिन । कर लगाने के लिए निम्नलिखित तीन चरण नोट किए गए:

> "दायित्व की घोषणा है, यह क़ानून का वह हिस्सा है जो यह निर्धारित करता है कि किस संपत्ति के संबंध में कौन से व्यक्ति उत्तरदायी हैं। आगे मूल्यांकन है. लिया योग्यता मूल्यांकन पर निर्भर नहीं करती. वह, परिकल्पना, पहले ही तय हो चुकी है। लेकिन मूल्यांकन विशिष्ट करता है

(43) (1926) एसी 3?

सटीक राशि जो उत्तरदायी व्यक्ति को चुकानी पड़ती है। अंत में, वसूली के तरीके आते हैं, यदि कर लगाने वाला व्यक्ति स्वेच्छा से भुगतान नहीं करता है।"

(96) *'चट्टूराम* बनाम *आयकर आयुक्त-बिहार* (44) और *छत्तूराम होरिलराम लिमिटेड* बनाम *आयकर आयुक्त बिहार और उड़ीसा* (45) और *खज़ान चंद* बनाम *राज्य के मामले* में संघीय न्यायालय द्वारा अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया था। *जे.* एवं *के.* (46)।

(97) *सभरवाल ब्रदर्स* बनाम *कमिश्नर, सेल्स टैक्स, यूपी (47)* में , जहां डीलर *एन को* पाया गया था: cto2 be2 *प्रामाणिक* 1 विवाद करते हुए कथित तौर पर समय के भीतर कर का भुगतान न करने के आधार पर देनदारी को ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया गया था। निर्दिष्ट.

(68) *कुरेशी क्रूसिबल सेंटर* बनाम *बिक्री कर आयुक्त (48)* में , शीर्षक *वी में* माना गया कि *के* जहां±करदाता ने यूपी बिक्री कर अधिनियम के तहत स्वीकृत कर जमा किया है। पिछले वर्षों के लिए कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कर की दर के निर्धारण के अनुसार, लेकिन कर निर्धारण प्राधिकारी ने खातों को खारिज कर दिया और उच्च दर पर कर की दर निर्धारित करते हुए एक सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन आदेश पारित किया और करदाता से ब्याज के भुगतान की भी मांग की । न्यायालय ने मांग को खारिज कर दिया और कहा, "मामले की परिस्थितियों में निर्धारिती पर ब्याज लगाने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकला कि निर्धारिती ने 7 प्रतिशत की दर से कर जमा न करके दुर्भावनापूर्ण कार्य किया /"

टी

(99) ब्याज या जुर्माने का भुगतान करने के दायित्व का निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए टर्न-ओवर की वापसी की तारीख से लेकर निर्धारित कर के अंतिम भुगतान तक की पूरी अवधि के लिए निर्धारिती के आचरण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ब्याज का भुगतान करने का दायित्व तभी उत्पन्न होता है जब कर का आकलन किया जाता है और वैधानिक अवधि के भीतर जमा नहीं किया जाता

है। ब्याज का भुगतान करने के लिए कार्रवाई का कारण अधिकारियों द्वारा निर्धारित या करदाता द्वारा सकारात्मक रूप से ज्ञात कर के भुगतान में चूक है। ब्याज लगाने का उद्देश्य सभी मामलों में समान रूप से लागू किया जाने वाला जुर्माना नहीं है

(44) (1947) 15 आईटीआर 202।

(45) (1955) 27 आईटीआर 709।

(46) 1984 (56) एसटीसी 214।

(47) एसटीसी (76) 41.

(48) (1986) 61 एसटीसी 327।

डिफ़ॉल्ट चाहे *वास्तविक हो* या अन्यथा। III *'अन्नपूर्णा बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और अन्य* बनाम *यूपी राज्य और, अन्य* (49), जहां एक डीलर को अधिकारियों के निर्णय के अनुरूप प्रासंगिक टर्न-ओवर पर उसके द्वारा देय कर की गणना करते हुए पाया गया, यह यह देखा गया कि उसे टैक्सी की गलत गणना करने के लिए नहीं ठहराया जा सकता। न्यायालय ने आगे कहा:-

> **"इसलिए, इसका मतलब यह है कि जहां एक डीलर ने विषय पर प्रचलित व्याख्या के अनुसार उसके द्वारा देय कर की गणना की है, तो यह कहना संभव नहीं होगा कि वह अधिनियम के तहत देय कर नहीं है। जब तक गणना अधिनियम के अनुरूप है तब तक डीलर पर कानून में बदलाव या उसकी व्याख्या के कारण अधिक पाई गई किसी भी राशि पर ब्याज का दायित्व नहीं डाला जा सकता है । अधिकारियों द्वारा पारित आदेश के परिणामस्वरूप भुगतान करने का दायित्व डीलर द्वारा देय कर की गणना के समान नहीं है। कानून में संशोधन या दृष्टिकोण में बदलाव के कारण इसके अलावा देय कोई भी राशि अतिरिक्त राशि है और इसे अधिनियम की धारा 8(1) के प्रयोजनों के लिए स्वीकार्य रूप से देय कर नहीं माना जा सकता है। जब तक**

गणना ईमानदार और उचित है तब तक डीलर ब्याज का भुगतान करने के लिए किसी भी दायित्व में शामिल होगा।

कल्लारेहल एजेंसियां बनाम *केरल राज्य और अन्य* (50) में केरल उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच । उन परिस्थितियों पर विचार किया गया जिनके तहत दंडात्मक ब्याज लगाया जा सकता है। मामले के तथ्यों से निपटना और कानून के प्रावधानों पर भरोसा करते हुए यह माना गया-

"उपधारा (3) के तहत दंडात्मक ब्याज की वसूली।" केरल सामान्य बिक्री कर अधिनियम की धारा 23* को इस आधार पर याचिकाकर्ता द्वारा इस मूल याचिका में चुनौती दी गई है कि याचिकाकर्ता ने नियम 18 के उप-नियम (1) के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत रिटर्न के अनुसार कर का भुगतान नहीं किया है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि उनके मामले में फॉर्म नंबर 14 में नियम 18 के उप नियम (3) के अनुसार मांग का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। हमने 1984 के ओपी नंबर 7804- *एम (जॉय वर्गीस* बनाम *केरल राज्य* (1986) 62 एसटीसी 227 (केर) में फैसला सुनाया है कि

(49) 1982 (50) एसटीसी 56।

(50) 1987 (65) एसटीसी 281,

ऐसी परिस्थितियों में दंडात्मक ब्याज का भुगतान करने का दायित्व केवल तभी बनता है जब केरल सामान्य बिक्री कर नियमों और फॉर्म के नियम 18 के उप-नियम (3) के अनुसार जारी मांग की सूचना के अनुसार मांगे गए कर की राशि का भुगतान करने में विफलता होती है। संख्या 14. जैसा कि आवश्यक था, मांग क कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है, याचिकाकर्ता पर मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा दंडात्मक ब्याज की वसूली और प्रदर्शन पी 3 के तहत दंडात्मक ब्याज की मांग का नोटिस और उसके द्वारा दायर संशोधन में आदेश प्रदर्शन पी -4 इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है। हम कहते हैं क मांग की सूचना के बिना दंडात्मक ब्याज लगाया गया है क्योंकि यह याचिकाकर्ता का मामला है, जो इस तथ्य से भी समर्थित है कि विवादित आदेश प्रदर्शनी पी-3 में मांग की सूचना का कोई संदर्भ नहीं है..."

(101) *बीर सेन आनंद और अन्य बनाम* जे एंड के *राज्य (51)* में , यह माना गया था कि बिक्री कर का भुगतान करने के लिए निर्धारिती की देनदारी तब उत्पन्न होती है जब उसने रिटर्न दाखिल किया था, न कि किसी बाद की घटना के घटित होने पर। मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति या अस्वीकृति या रिटर्न या मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा किए गए मूल्यांकन पर जहां उसने रिटर्न दाखिल नहीं किया है। निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किया गया मूल्यांकन कर का भुगतान करने के लिए उसकी देनदारी की *पूर्वव्यापी घोषणा होगी।* कर के भुगतान में देरी के लिए मुआवजे के रूप में ब्याज केवल बिक्री कर देय होने की तारीख से अर्जित होता है, किसी भी पहले की तारीख से नहीं।

(102) *मेसर्स हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड* में वी. *उड़ीसा राज्य* (52)। सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा बिक्री कर अधिनियम के प्रावधानों के तहत जुर्माना लगाने के लिए प्रासंगिक विचारों पर विचार किया और माना कि जुर्माना का भुगतान करने का दायित्व केवल डीलर के पंजीकरण में डिफ़ॉल्ट के प्रमाण पर उत्पन्न नहीं होता है। आगे कहा गया, "आमतौर पर जुर्माना तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि

पार्टी जानबूझकर या कानून की अवहेलना करने के लिए बाध्य न हो या अपमानजनक या बेईमान आचरण का दोषी हो , या अपने दायित्व के प्रति सचेत उपेक्षा में काम न करे। जुर्माना भी केवल इसलिए नहीं लगाया जाएगा क्योंकि ऐसा करना वैध है।"

(103) अधिनियम की धारा 25 की उपधारा 5 के तहत, विधानमंडल ने स्पष्ट रूप से परिस्थितियों की परिकल्पना की है

जिस पर निर्धारिती को कर की राशि पर ब्याज का भुगतान करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है। इस तरह की देनदारी केवल तभी तय की जा सकती है, जहां निर्धारिती को उसके तहत लगाए गए उचित कर के भुगतान से बचने के उद्देश्य से अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने का प्रयास करते हुए दिखाया गया है।

(104) अब यह अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है कि जुर्माना या ब्याज लगाने से संबंधित प्रावधानों को क़ानून की शर्तों और भाषा के भीतर समझा जाना चाहिए और इसकी यथास्थिति के अनुसार व्याख्या की जानी चाहिए। संदेह की स्थिति में, व्याख्या ऐसे तरीके से की जानी आवश्यक है जो करदाता के अनुकूल हो। यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कर प्रावधान की भाषा अस्पष्ट है या एक से अधिक अर्थ निकालने में सक्षम है, तो न्यायालय को उस व्याख्या को अपनाने की आवश्यकता है जो निर्धारिती के पक्ष में हो, खासकर जब प्रावधान जुर्माना या ब्याज लगाने से संबंधित हो।

(105) मामले की कानूनी स्थिति और स्वीकृत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता-निर्धारिती ने *दुर्भाविनापूर्ण* या जानबूझकर कर का भुगतान करने से परहेज किया है और इस प्रकार उप-धारा 5 के अर्थ के तहत ब्याज का भुगतान करने का दायित्व वहन किया है। अधिनियम की धारा 25. ब्याज के भुगतान के संबंध में मांग भी अस्पष्ट, संदिग्ध और कानून के अधिकार के बिना है। याचिकाकर्ताओं को अधिनियम के प्रावधानों के तहत खरीद कर के भुगतान के लिए की गई वास्तविक मांग से पहले किसी भी अवधि के लिए ब्याज का भुगतान करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है। विवादित आदेश जहां तक यह निर्देशित करता है कि यदि ब्याज का भुगतान रद्द किया जा सकता है तो भुगतान रद्द कर दिया जाएगा। यह किसी भी तरह से निर्धारिती को मांग नोटिस की तारीख से कर पर ब्याज का भुगतान करने से नहीं रोकता है, क्योंकि उस दिन उन्हें कर का भुगतान करने की अपनी देनदारी के बारे में पता था, लेकिन जानबूझकर झूठे बहाने से भुगतान करने से बचते रहे और अनावश्यक मुकदमेबाजी का सहारा लेकर तकनीकी जटिलताओं के तहत दलीलें देना।

(106) मामले में एक और बिंदु पर बहस की गई। परिस्थितियों के अंतर्गत . यह आयोजित किया जाता है : -

(i) 1991 के हरियाणा अधिनियम संख्या 4 के प्रावधान कानूनी, वैध और संवैधानिक हैं;

(ii) **1993** के अधिनियम संख्या **9** द्वारा प्रतिस्थापित अधिनियम की धारा 15-ए के प्रावधान संविधान के प्रावधानों के अधिकार *क्षेत्र के अंतर्गत* हैं और याचिकाकर्ताओं पर पूर्वव्यापी रूप से खरीद कर का भुगतान करने का दायित्व थोप रहे हैं।

(iii) **अधिनियम की धारा 9 को वैध रूप से हटा दिया गया था और इस धारा ने याचिकाकर्ताओं को मांगे गए कर के भुगतान से कोई छूट नहीं दी थी;**

(iv) **याचिकाकर्ता धान की भूसी के लिए उनके द्वारा उपयोग किए गए धान पर खरीद कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं, जिसे अंततः देश से बाहर निर्यात किया गया था।**

(v) **अनुबंध पी/एल, अधिनियम की धारा 40 के तहत नोटिस कानूनी, वैध और कानून के अनुसार है,**

(vi) **अधिनियम की धारा 28, 29, 31 और 33 के तहत मूल्यांकन और मांग का विवादित नोटिस जहां तक खरीद कर के भुगतान का निर्देश देता है, कानूनी, वैध और कानून के अनुसार है। हालाँकि, याचिकाकर्ताओं को मूल्यांकन और मांग के उक्त नोटिस में निर्दिष्ट ब्याज की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया गया है। मूल्यांकन प्राधिकारी अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा 5 के संदर्भ में ब्याज का भुगतान करने के लिए याचिकाकर्ताओं के दायित्व को नए सिरे से निर्धारित करेगा, लेकिन ब्याज केवल मूल्यांकन की सूचना और किसी अंतरिम रोक के बावजूद मांग की तारीख से लगाया जाएगा। हरियाणा**

राज्य में किसी भी न्यायालय द्वारा दी गई,

. (107) सिविल रिट याचिका संख्या 6071, 6073, 6072, 7572. 6074, 7575, 7576, 7578, 13981, 1993 की 7574, 11422. 14755, 1994 की और 1996 की 1995 उपरोक्त शर्तों में निस्तारित की जाती है। मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय केवल वादकर्ता के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह इसे अपनी भाषा में समझ सके और इसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी न्यायिक और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए मान्य होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

हिमानी सागर

प्रशिक्षित न्याय अधिकारी, हरियाणा